www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 25 अंक : 04 | गोरखपुर, 20 जुलाई 2025 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

▶ प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क अपने अंतिम स्वरूप की ओर अग्रसर

योगी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की तीन ईकाइयां लोकार्पण के लिए तैयार

▶ लागत का 25 प्रतिशत अनुदान केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा

प्रतीक चित्र साभार सोशल मीडिया

गोरखपुर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के सेक्टर 28 में प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क आकार लेने लगा है। यहाँ प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली तीन ईकाइयां लोकार्पण के लिए बनकर तैयार हैं। इन तीनों ईकाइयों में कुल मिलाकर करीब 120 करोड़ रुपए की धनराशि का निवेश हुआ है और इससे 300 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से योगी सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप होने से प्लास्टिक पार्क परियोजना निवेशकों पहली पसंद रहा है। यहां 60 से अधिक भूखंड आवंटित हो चुके है।

प्लास्टिक पार्क, प्लास्टिक उत्पादों से जुड़ी ईकाइयों को को एक क्लस्टर के रूप में विकसित करने की विशेष परियोजना है। केंद्र सरकार के रसायन एवं पेट्रो-केमिकल्स विभाग ने प्लास्टिक के विश्व व्यापार में भारत की साझेदारी को बढ़ाने एवं क्लस्टर विकास के माध्यम से प्लास्टिक पार्क योजना विकसित की है। इस योजना के तहत देश भर मे 10 प्लास्टिक पार्कों को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। इसी योजना के तहत उत्तर प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे गीडा द्वारा अधिग्रहित ग्राम नरकटड़ा की 88 एकड़ भूमि पर बसाया गया है। गीता में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत प्लास्टिक पार्क परियोजना की कुल लागत 69.58 करोड़ रुपये है। लागत का 25 प्रतिशत अनुदान केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

गीडा में विकसित हो रहे इस परियोजना में 92 प्लास्टिक उत्पाद की इकाइयों के लिए विभिन्न क्षेत्रफल के आवंटन हेतु उपलब्ध भूखंडों में से पांच दर्जन से अधिक भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है। शेष बचे 31 भूखंडों के आवंटन के लिए भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उद्यमियों के रुझान एवं दो वर्षों में ही आवंटन के दृष्टिगत यह भारत की सर्वाधिक सफल प्लास्टिक पार्क परियोजनाओं में से एक सिद्ध हुआ है। प्लास्टिक पार्क में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओ (सिविल एवं विद्युत) के विकास के तहत सीसी रोड, आरसीसी ड्रेन-कलवर्ट, चारदीवारी, बिजली घर का निर्माण कार्य पूर्ण है।

गीडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुज मलिक के अनुसार, प्लास्टिक पार्क में कुछ ईकाइयों में उत्पादन भी शुरू हो चुका है। इन्हीं उत्पादनरत कंपनियों में से 120 करोड़ रुपए के निवेश की तीन इकाइयों का लोकार्पण जल्द ही किया जाना प्रस्तावित है। इसमें प्लास्टिक पैकेजिंग की प्रमुख कंपनी टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी ने 20 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल का भूखंड लेकर 96 करोड़ रुपए का निवेश किया है। दो वर्ष में ही काम पूरा होने के बाद यहाँ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। इस यूनिट में 250 लोगों को रोजगार मिला है।

इसके अलावा गीडा द्वारा प्लास्टिक पार्क में ओम फ्लैक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को 4150 वर्गमीटर जमीन का आवंटन प्लास्टिक पाइप्स उत्पादन के लिए किया गया है। ओम फ्लैक्स द्वारा 17.00 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जिसमे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 50 लोगो को रोजगार की प्राप्ति हुई है। साथ ही गजानन पॉली प्लास्ट ने 1196.00 वर्गमीटर जमीन लेकर 7 करोड़ रुपए के निवेश से यूनिट की स्थापना की है। इसमें 25 लोगों को रोजगार मिला है।

प्लास्टिक पार्क में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान (सीपेट) द्वारा 16 करोड़ रुपए की लागत से स्किल ट्रेनिंग सेंटर और कामन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाना है। इसके लिए गीठा द्वारा सीपेट को पांच एकड़ भूमि निशुल्क दी गई है। यहाँ सीपेट द्वारा प्लास्टिक उद्योग में कौशल विकास एवं सेवायोजन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

हिमाचल में हुई अनोखी शादी, जिसकी हर जगह हो रही चर्चा

दो सगे भाइयों ने एक ही युवती के साथ लिए 7 फेरे...विवाह बहुपति विवाह परंपरा पर आधारित था

सिरमौर। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई गांव में हाल ही में एक अनोखी शादी ने सबका ध्यान खींचा, जहां एक दुल्हन ने दो भाइयों से विवाह रचाया। शिलाई गांव के प्रदीप नेगी और कपिल नेगी ने नजदीकी कुनहाट गांव की सुनीता चौहान से एक साथ विवाह किया। यह विवाह समारोह पूरी सहमति और सामुदायिक भागीदारी के साथ सम्पन्न हुआ। यह आयोजन हाटी समुदाय की बहुपति (पॉलीएंड्री) परंपरा पर आधारित था, जिसमें एक ही पत्नी को दो या अधिक भाई साझा रूप से अपनाते हैं।

ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, प्रदीप नेगी जल शक्ति विभाग में कार्यरत हैं और उनके छोटे भाई कपिल विदेश में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कार्यरत हैं। हालांकि दोनों की दिनचर्या और देश अलग हैं। फिर भी दोनों भाइयों ने मिलकर इस परंपरा को निभाने का निर्णय लिया। प्रदीप ने कहा कि यह हमारा संयुक्त निर्णय था। यह विश्वास, देखभाल और साझी जिम्मेदारी का रिश्ता है। हमने इस परंपरा को खुले तौर पर अपनाया क्योंकि हमें अपनी जड़ों पर गर्व है। वहीं कपिल ने कहा कि मैं भले ही विदेश में हूं, लेकिन इस विवाह के माध्यम से हम अपनी पत्नी को स्थिरता, समर्थन और प्रेम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दुल्हन सुनीता का कहना है कि यह मेरा स्वयं का निर्णय था। मुझ पर कोई दबाव नहीं था। मैं इस परंपरा को जानती हूं और इसे अपनी इच्छा से अपनाया है। बता दें कि इस अनूठी शादी में सैकड़ों गांववाले और रिश्तेदार शामिल हुए। तीन दिन तक चले समारोह में पारंपरिक ट्रांस-गिरी व्यंजन परोसे गए और पहाड़ी लोकगीतों पर नृत्य करते ग्रामीणों ने शादी को उत्सव का रूप दे दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे गांव में ही तीन दर्जन से अधिक परिवारों में दो या तीन भाइयों की एक पत्नी होती है। लेकिन ऐसी शादियां आमतौर पर चुपचाप होती हैं। यह शादी ईमानदारी और गरिमा के साथ सार्वजनिक रूप से मनाई गई, जो इसे खास बनाती है।

ट्रांस-गिरी क्षेत्र में पॉलीएंड्री की परंपरा के पीछे कई व्यावहारिक कारण रहे हैं। जैसे पुश्तैनी जमीन का विभाजन रोकना, महिलाओं को विधवा होने से बचाना और परिवार में एकता बनाए रखना। खासकर तब जब भाइयों को काम के लिए दूर जाना पड़ता था। अब जबकि हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल चुका है।

▶ राजस्थान पुलिस का बड़ा खुलासा : अमेरिका से आए कोयले में मिलावट, करोड़ों का घोटाला उजागर

सिरोही में नकली कोयला पाउडर डस्ट मिलाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पदार्फास; एक गिरफ्तार, करोड़ों का माल जब्त

जयपुर। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार के निर्देशन में इन दिनों कई बड़ी-बड़ी कार्यवाहियों को अंजाम दिया जा रहा है। राजस्थान पुलिस की सीआईडी क्राइम ब्रांच राजस्थान ने अवैध गतिविधियों और संगठित अपराधों के खिलाफ अपनी मुहिम में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध दिनेश एम एन के नेतृत्व में एक ऐसे शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है जो वरअ से आयातित उच्च गुणवत्ता वाले कोयले (पेटकॉक) में मिलावट कर रहा था। इस गोरखधंधे से सीमेंट और स्टील फैक्ट्रियों को करोड़ों रुपये का चूना लगाया जा रहा था।

एडीजी एमएन ने बताया कि सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम को पिछले कुछ समय से यूएसए से आयातित उच्च गुणवत्ता वाले कोयले (पेटकॉक) की चोरी की सूचनाएं मिल रही थीं। मुखबिरों से मिली जानकारी के अनुसार गुजरात के कुछ कोयला माफियाओं ने पिण्डवाड़ा-आबूरोड नेशनल हाईवे 27 पर भुजेला स्थित तुलसी होटल के पीछे एक बंद पड़ी फैक्ट्री किराए पर ले रखी थी। ये शातिर अपराधी ट्रक ड्राइवरों को मोटी रकम का लालच देकर उनके ट्रकों से 5 से 10 टन शुद्ध विदेशी कोयला निकलवा लेते थे और उसकी जगह उतनी ही मात्रा में नकली कोयला पाउडर डस्ट मिला देते थे। चोरी किए गए इस बेशकीमती कोयले को गिरोह द्वारा छोटी औद्योगिक इकाइयों को बेचकर लाखों रुपये की अवैध कमाई की जा रही थी।

उप महानिरीक्षक पुलिस अपराध योगेश यादव के समन्वय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरोत्तम वर्मा के सुपरविजन में हेड कांस्टेबल रमेश कुमार की सूचना पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक फूलचंद टेलर और पुलिस

निरीक्षक रामसिंह ने किया। टीम ने बीते शुक्रवार को थाना रोहिडा सिरोही को सूचित कर यह कार्रवाई कराई। पुलिस में भुजेला हाईवे स्थित तुलसी होटल के पीछे की फैक्ट्री परिसर में धावा बोला। मौके से पुलिस ने दो ट्रक, एक लोडर, एक डोजर मशीन और कोयले से भरे ट्रक की सील तोड़ने का सामान जब्त किया।

कार्रवाई के दौरान इरफान पुत्र हारून (32) निवासी मदिना सोसायटी लाजपथ नगर पुलिस थाना राधनपुर जिला पाटन गुजरात को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी इरफान ने जो खुलासा किया, वह बेहद चौंकाने वाला था। उसने बताया कि वे ट्रक ड्राइवरों से 5-7 हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से कोयला खरीदते थे और ट्रक में नकली डस्ट कोयला मिलाकर आगे भेज देते थे। इस तरह वे प्रतिदिन लगभग 15-20 टन कोयले की चोरी कर रहे थे, जिससे उन्हें रोजाना लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की मोटी कमाई हो रही थी। सफल कार्यवाही में शामिल प्रमुख टीम के सदस्यों में पुलिस उपाधीक्षक फूलचन्द टेलर, पुलिस निरीक्षक रामसिंह नाथावत, सहायक उपनिरीक्षक बनवारीलाल, दुष्यन्त सिंह, हेड कांस्टेबल महेश सोमरा, शाहीद अली, राकेश कुमार, रमेश कुमार, हेमन्त शर्मा, महावीर, कांस्टेबल महेंद्र सिंह, कांस्टेबल चालक राजेश कुमार, पुलिस निरीक्षक रेन्ज सैल उदयपुर हिमांशु सिंह, हेड कांस्टेबल दिनेश, कांस्टेबल हिम्मत सिंह, थानाधिकारी रोहिड़ा माया पण्डित, हेड कांस्टेबल देवाराम, कांस्टेबल शंकरलाल, रमेश कुमार और चालक कांस्टेबल मोरमुकुट शामिल थे। हेड कांस्टेबल रमेश कुमार की सूचना इस कार्रवाई में निर्णायक साबित हुई।

नजर नजर में फर्क

नजर नजर में होता है फर्क बहुत
कोई नजरें होकर भी है अंधा
देखकर भी कर देता है कोई अनदेखा
दुनियां में सब मतलब का है धंधा
मां की नजर में है ममता ही ममता
पिता की नजर में त्याग है बसता
जमाने की नजर में है स्वार्थ नजर आता
प्यार का दिखावा करके पीठ पीछे से है डसता
नजरें भी कई बार खा जाती हैं धोखा
कई बार सच नहीं होता जो है नजर आता
सच्चाई कुछ और होती है
आदमी धोखा है खा जाता
नजरें किसी से जब होती हैं चार
मिलने को दिल हरपल रहता है बेकरार
नजरें ही जब बुढ़ापे में दे जाती हैं धोखा
देख नहीं पाते हो जाता चलना दुश्वार
नजर अच्छी है तो सब अच्छा है लगता
बुराई में भी अच्छाई नजर है आती
नजरें यदि थोड़ी भी हैं खराब
तो अच्छाई में भी बुराई है दिख जाती
नजर भी कई बार खा जाती है धोखा
इसलिए दिमाग का करना इस्तेमाल
दुनियां की हर शय में अच्छाई देखना
यह भी तो है हमारी नजर का कमाल

रवींद्र कुमार शर्मा
घुमारवीं
जिला बिलासपुर हि प्र

न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

बेंगलुरु। न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने शनिवार को बेंगलुरु के राजभवन में आयोजित एक समारोह में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राजभवन परिसर स्थित ग्लास हाउस में नए मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाई। इस समारोह में न्यायपालिका और राज्य सरकार के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू को भी राज्यपाल ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और विधान परिषद के सभापति बसवराज होरट्टी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और नए मुख्य न्यायाधीश को बधाई दी। इस कार्यक्रम में पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव सहित कर्नाटक उच्च न्यायालय के कई न्यायाधीश भी उपस्थित थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में, विभु बाखरू कर्नाटक राज्य में न्याय प्रशासन की देखरेख करेंगे और बेंगलुरु में उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ की अध्यक्षता करेंगे।

न्यायमूर्ति बाखरू की नियुक्ति उनके विशिष्ट करियर के बाद हुई है, हाल ही में वे दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश के पद पर उनकी पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उनके नाम की सिफारिश के बाद हुई। न्यायमूर्ति विभु बाखरू का जन्म 1966 में नागपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, नई दिल्ली से प्राप्त की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद, उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में छात्र के रूप में दाखिला लिया और 21 मार्च, 1985 को ठाकर, वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी के साथ अपना लेखन कार्य शुरू किया। उन्होंने 1987 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की तथा 1989 में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की।

उन्होंने 1990 में एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और सितम्बर 1990 में दिल्ली बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, कंपनी लॉ बोर्ड और विभिन्न अन्य न्यायाधिकरणों में वकालत की। उन्हें 28 जुलाई, 2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया था। उन्हें 17 अप्रैल, 2013 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और 18 मार्च, 2015 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 5 दिसंबर, 2024 से 21 जनवरी तक दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी नियुक्त किया गया था।

निरोगी महिला अभियान की शुरुआत

पुणे। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को यहां महिला स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए उपमुख्यमंत्री निरोगी महिला अभियान की शुरूआत की। इस अभियान का उद्देश्य बड़े पैमाने पर जांच के माध्यम से गर्भाशय ग्रीवा और स्तन कैंसर जैसी बीमारियों का शीघ्र पता लगाना और उनकी रोकथाम करना है।

तीन महीने तक चलने वाली इस पहल का उद्देश्य महाराष्ट्र भर में पांच लाख से ज्यादा महिलाओं की जांच करना है और उनमें गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का पता लगाना है जो दुनिया भर में महिलाओं को होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है। यह पहल ठाणे नगर निकाय, रोटरी क्लब और आदित्य बिड़ला कैपिटल फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित की जा रही है। इस अवसर पर शिंदे ने कहा, ह्यह्यअपनी बहनों को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है।

सायरा बानो राजेंद्र कुमार के इश्क में गिरफ्तार हो गई थीं

पहली बार जोड़ी बनी तो उन्हें नाकारा कहकर बाहर कर दिया गया, मगर दूसरी बार ऐसा कमाल हुआ कि राजेंद्र कुमार ने जीवन भर आशा पारेख को कहा, 'भाग्यलक्ष्मी'। वर्ष 1961 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'घराना' कनाडा तक में प्रदर्शित हुई। राज कुमार, राजेंद्र कुमार और आशा पारेख अभिनीत यह फिल्म 1960 की तेलुगु फिल्म 'शांति निवासम्' की रीमेक थी!

1963 में आई सीवी श्रीधर निर्देशित फिल्म 'दिल एक मंदिर' में राजेंद्र कुमार ने कैंसर विशेषज्ञ का किरदार निभाया था। 'रुक जा रात ठहर जा रे चंदा', 'हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे' जैसे गीतों से सजी इस फिल्म में मीना क मारी के साथ उनकी जोड़ी खूब पसंद की गई और राजेंद्र कुमार नामिनेट हुए फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर के लिए। मेरे महबूब : जिससे हुई 'साधना कट की शुरूआत

अशोक कुमार, साधना, प्राण, जानी वाकर जैसे कलाकारों से सजी इस फिल्म में साधना को जिस गीत 'मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत की कसम' के माध्यम से राजेंद्र कुमार ने प्रपोज किया था, फिल्म का निर्देशन एच. एस. रवैल हासिल कर लिया था। क्या खूब दोस्ती सबसे सफल फिल्म थी। इसी फिल्म में दिलीप कुमार आए तो किस्मत ने ऐसा खेल पलटा कि सायरा दिलीप की ही होकर रह गईं। इस फिल्म ने खलनायक के रूप में नजर आए धर्मेंद्र की भी किस्मत बदल दी थी। राजेंद्र कुमार इसी साल की सबसे सुपरहिट फिल्म का हिस्सा भी थे और फिल्म थी राज कपूर और वैजयंती माला के साथ त्रिकोणीय प्रेमकहानी 'संगम'। साल 1966 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली राजेंद्र कुमार और वैजयंतीमाला की इस फिल्म का संगीत शंकर-जयकिशन ने तैयार किया था, गीत शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने लिखे थे। 'बहारों फूल बरसाओ' बरात का सदाबहार गीत बना तो, वहीं इसका 'तितली उड़ी, उड़ जो चली' को नए-नए अवतार में आज भी सुना जा सकता है। साल 2013 में बीबीसी रेडियो ने सर्वे में हिंदी फिल्म इतिहास के अब तक के 100 सर्वश्रेष्ठ गीतों की, सूची में 'बहारों फूल बरसाओ' पहले नंबर पर रखा गया था। 1968 में आई रोमांटिक-कामेडी फिल्म 'झुक गया आसमान' हालीवुड फिल्म 'हियर कम्स मिस्टर जार्डन' पर आधारित थी और इसका एक गाना था एल्विस प्रेस्ले के एलबम 'मार्गरीटा' से। वही जिसे आप मोहम्मद रफी की आवाज में 'ओ प्रिया' सुनते हैं। एक दुर्घटना और धर्मराज के दूत से हुई गलती के इर्द-गिर्द सजी इसकी कहानी जितनी नई थी, उतनी ही दर्शकों के दिल के करीब आ गई। 'उनसे मिली नजर' व 'कौन है जो सपने में आया' जैसे गीतों पर दर्शकों ने खूब प्यार लुटाया और इसे सिल्वर जुबली बना दिया।

वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हाल में शूट हुआ है। 1963 में आई इस ने किया था। प्रदर्शित होते ही इसने उस साल बाक्स आफिस पर पहला दर्जा निभाई दिलीप साहब ने 1964 में प्रदर्शित 'आई मिलन की बेला' साल की दूसरी काम करते हुए सायरा बानो राजेंद्र कुमार के इश्क में गिरफ्तार हो गई थीं। जब उन्हें समझाने

'त्रिमाया': अपनी पड़ोस की दुनिया को एक नई निगाह से देखने का आमंत्रण

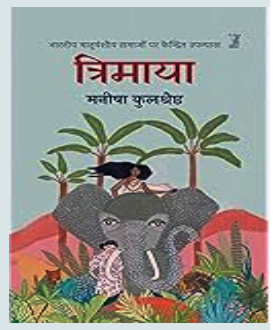

कुछ कथाएं किसी विचार या किसी अनूठे क्षण की उपज भर नहीं होतीं, बल्कि जीवन की जिज्ञासाएं, अनुभव और अवलोकन, जब एक लय में गूंजने लगता है, तब वे अपना स्वरूप धारण करती हैं। कथाकार मनीषा कुलश्रेष्ठ की 'त्रिमाया' एक ऐसी ही संवेदनशील कथा है, जिसमें उन्होंने ऐसा विषय चुना है, जो बहुधा इतिहास की परछाइयों में गुम रहा- भारतीय समाज में मातृसत्ता और मातृवंश की परंपरा... ये उपन्यास केवल उन समुदायों की गाथा नहीं है, जहां स्त्रियां वंश की वाहक रही हों, बल्कि यह उन छूटे हुए प्रश्नों की भी कथा है, जिन्हें पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने कभी उठाने की जरूरत नहीं समझी। यह असम के घने जंगलों, मेघालय की भीगी बाजार गलियों, त्रिवेंद्रम के पुराने थारवाड़ों और जलदापारा के हाथियों तक फैली एक ऐसी स्मृति यात्रा है, जहां स्त्री, समाज की परिधि से निकलकर संरचना का मूल बनती है। मनीषा कुलश्रेष्ठ ने खासी, गारो और नायर समाजों की मातृवंशी संरचना को जिस संवेदना, शोध और कथा-कौशल से बुना है, वह हिंदी उपन्यासों की दुनिया में अलग स्थान रखता है। औपन्यासिक कर्म के लिए मनुष्य समाज के साथ जीव-जंतुओं के जीवन को तीक्ष्ण दृष्टि से देखने की दृष्टि ने मातृवंशीय समाज के उन सरोकारों की शिनाख्त की है, जो संसार में स्त्रियों के भूगोल और मनोदशा की बात करता है। भले ही उसमें एक हथिनी भी पूरी स्वायत्तता के साथ एक किरदार बनती हो।

तीन समानांतर कथाओं में बंटी हुई 'त्रिमाया' का फलक वहां जाकर विस्तार पाता है, जहां स्त्री स्वीकार्य के लिए हमारे समाज में स्थान दिलाने की पहल की गई है। पहली माया, एक हथिनी है, जो मातृवंशी समाज की कुलमाता है। दूसरी माया, केरल के परिवेश के नायर समाज को जानने की इच्छुक आई.ए.एस. ट्रेनी के रूप में मौजूद है और तीसरी माया, शिलांग के खासी समुदाय की एक औरत है, जो अपने बेटों के विरोध के बावजूद अपने पति की नाजायज बेटी को मातृवंश की परंपरा के अनुसार अपनी संपत्ति देने का निर्णय करती है। तीनों ही कहानियां उस एक मनके से बंधी हुई हैं, जहां पाने और गंवा देने के बीच स्त्रियों का अपना जीवन पूरी उदात्तता के साथ खुद का समाज और परिवेश निर्मित करता है। यहां प्रकृति, प्रेम, अधिकार, वर्जनाएं, मुक्ति, संघर्ष और स्वप्न सभी कुछ आपस में गड्डमड्ड होकर ऐसा खेल खेलते हैं, जिसमें स्त्री की अपनी स्वनिर्मिति महत्वपूर्ण बन जाती है। यहां हथिनी का जीवन भी इतने विराट ढंग से सामने आता है कि उसके आगे विडंबनापूर्ण ढंग से नगरीय जीवन की स्त्रियों का एकाकीपन बदरंग लगने लगता है। 'त्रिमाया', दरअसल अपनी पड़ोस की दुनिया को एक नई निगाह से देखने का आमंत्रण है, जिसमें मातृवंशी समाज की संघर्षगाथा, मनुष्य के विरोधाभासों और सामाजिक सद्भाव के प्रश्नों से सीधा मुठभेड़ करती है। किसी दिन पितृसत्ता के विफल होने की कल्पना के साथ, मातृसत्तात्मक समाज की भोर का सपना देखती कृति !

विश्वविद्यालय व युवा चेतना समिति के तत्वाधान में चेतन वाटिका की पहल

गोरखपुर । दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं युवा चेतना समिति के संयुक्त तत्वावधान में भूगोल व मनोविज्ञान विभाग के बीच युवा चेतना वाटिका की पहल को साकार करते हुए वृक्षारोपण किया गया. इसकी खास बात है कि यह गोरखपुर विश्वविद्यालय की पहली आर्किटेक्टेड वाटिका है. यह वाटिका कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन के विजन, डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर अनुभूति दुबे के एग्जीक्यूशन का परिणाम है. यह वाटिका युवा चेतना समिति के 25 वर्ष का हरित स्मारक भी होगी. इस पहल को साकार करने में मनोविज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर धनंजय कुमार तथा भूगोल विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शिवाकांत सिंह की सक्रिय भूमिका रही।

इस अवसर पर मनोविज्ञान विभाग में आयोजित विचार गोष्ठी के दौरान मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा कि विश्वविद्यालय के अकादमिक वातावरण के उन्नयन में प्राकृतिक हरीतिमा की बड़ी भूमिका होती है. गोरखपुर विश्वविद्यालय एक ऐसा विलक्षण विश्वविद्यालय है, जिसके पास शहर के बीचो-बीच 191 एकड़ का परिसर है, जिसमें हरियाली की अपार संभावनाएं हैं. इसको ध्यान में रखते हुए हम वृक्षारोपण

कार्यक्रम को एक व्यवस्थित रूप से प्रदान कर रहे हैं जिसके तहत वाटिका के कांसेप्ट को धरातल पर उतारा जा सकता है। जो किसी तरह के जंगल-झाड़ी से भिन्न एक व्यवस्थित (क्यूरेटेड एवं कल्टीवेटेड) धारणा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शहर के प्रतिष्ठित साहित्यकार एवं पूर्व आईआरटीएस अधिकारी रणविजय सिंह ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा में प्राकृतिक वातावरण पर विशेष रुप से ध्यान दिया गया है। युवा चेतना समिति के संरक्षक प्रो. शिवशरण दास ने अपने संबोधन में विशेष रूप से उल्लेख किया है कि मौजूदा कुलपति प्रो. पूनम टंडन गोरखपुर के नागर समाज के साथ संवाद में गहरी दिलचस्पी लेती हैं निरंतर कोशिश होती है कि विश्व विद्यालय को समाज के साथ और समाज को विश्वविधालय को साथ बेहतरीन ढंग से जोडा जा सके। उनके संवाद धर्म व्यक्तित्व का ही परिणाम है आज की युवा-चेतना वाटिका अधिष्ठाता व छात्र कल्याण प्रो. अनुभूति दुबे ने अपने संबोधन से सुनिश्चित किया कि विश्व विद्यालय परिसर में अब कोई भी वृक्षारोपण कार्यक्रम सुव्यवस्थित रूप में होगा। वाटिका का विचार ही इसका प्रमाण है। मनोविज्ञान तथा भूगोल विभाग के अध्यक्ष द्रव्य ने क्रमशः अपने संबोधन में वाटिका के उन्नयन व संरक्षण का विश्वास दिलाया। कार्यक्रम का संचालन युवा चेतना समिति के विनोद प्रकाश पांडेय, वाटिका की आर्किटेक्ट शिवानी पांडेय तथा आभार ज्ञापन मांधाता सिंह ने किया।

'क्या करना है? इस बारे में मैंने कोई सीमा तय नहीं की: मधु

अभिनेत्री मधु अब अपने पेशेवर सफर की दूसरी पारी में नए आयाम तलाश रही हैं। वह ऐसी स्याह भूमिकाएं निभाना चाहती हैं, जैसा लोगों को उनसे उम्मीद ही ना हो। मधु हमेशा से इस बात को लेकर स्पष्ट रही हैं कि उन्हें क्या नहीं करना है। वह कहती हैं, 'क्या करना है? इस बारे में मैंने कोई सीमा तय नहीं की। हां, इस बात को लेकर सुनिश्चित हूं कि क्या नहीं करना है। जैसे अगर कोई आउटफिट मुझे सूट नहीं करता या मैं नहीं पहनना चाहती तो उसे मैं कभी नहीं पहनूंगी। सेट पर कलाकारों को मिलने वाली सुविधाएं हों या फीस, उन सबमें मुझे बराबरी चाहिए। किसी मित्र के लिए मैं फ्री में भी काम कर लूंगी। वहीं अगर फीस लेकर कर रही हूं, तो फीस वही होनी चाहिए, जिसकी मैं हकदार हूं।' फिल्म 'दिलजले' में मधु ने पहली बार शबनम की स्याह भूमिका निभाकर लोगों की उम्मीदों से कुछ अलग किया था। अब वह फिर ऐसा ही कुछ करना चाहती हैं। इस संदर्भ में वह कहती है, 'उन दिनों धारणा थी कि लीड हीरोइन नकारात्मक भूमिकाएं नहीं निभाती है। जब शबनम का रोल आया था, तो पापा और मैनेजर दुग्गल जी दोनों ने मना किया था। उनको लगता था कि ऐसी भूमिकाएं करने के बाद फिर हीरोइन नहीं बन सकते हैं। मुझे स्याह भूमिकाएं निभाना पसंद है। इसी कारण मुझे वो करने में और मजा आया था। लोग मुझे अक्सर अपने आस-पास की अच्छी लड़की के नजरिए से देखते हैं जबकि मैं ऐसी भूमिका निभाना चाहती हूं, जिसकी लोग मुझसे उम्मीद न करते हों। ऐसी भूमिकाओं में जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। एक चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है।'

▶ बाल आप्टे की पुण्य स्मृति दिवस पर डॉ. राकेश मिश्र की पुस्तक 'समिधा' का हुआ लोकार्पण

नई पीढ़ी को विरासत से अवगत कराएगी यह पुस्तक: डॉ. राकेश मिश्र

नई दिल्ली। शिक्षाविद डॉ. राकेश मिश्र की सद्यः प्रकाशित पुस्तक 'समिधा' का लोकार्पण गत दिनों 17 जुलाई 2025 (गुरुवार) को देश की राजधानी दिल्ली में संसद मार्ग स्थित एनडीएमसी के कान्वेंशन सेंटर में सम्पन्न हुआ। पुस्तक का लोकार्पण मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। इस अवसर विभिन्न क्षेत्र के लोग उपस्थित थे। लोकार्पित पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली के द्वारा किया गया है। महान राष्ट्रवादी चिंतक, प्रख्यात विधिवेत्ता एवं पूर्व सांसद बाल आपटे की पुण्य स्मृति दिवस को देखते हुए इसी तिथि को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेखक डॉ. राकेश मिश्र 10 वर्षों तक स्वर्गीय आपटे के सहायक के रूप में उनके साथ रहे। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि श्रीमती निर्मला बलवंत आप्टे स्वास्थ्य कारणों से अनुपस्थित रहीं, लेकिन उन्होंने डिजिटल माध्यम से आशीष वचन देकर डॉ. राकेश मिश्र के एवं प्रो. आप्टे की निकटता की चर्चा की।

उपयोगी आलेखों का संग्रह है समिधा: बतौर मुख्य अतिथि दत्तात्रेय होसबाले ने डॉ. राकेश मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक का लोकार्पण करते हुए कहा कि इस पुस्तक में संकलित सभी 50 आलेख अलग-अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन की प्रमुख बातों को बेहद ही रोचक तरीके से इस पुस्तक दर्शाया गया है। प्रो. बाल आप्टे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित कई सामाजिक पहलुओं पर लिखी गई यह पुस्तक चेतना जागृत करेगी। विभिन्न विषयों पर चिंतन कर उसको पुस्तक का रूप देना एक बड़ी उपलब्धि है। इस संकलन के लिए डॉ. राकेश मिश्र के प्रयास की प्रशंसा करते हुए उनके सामाजिक एवं सांगठनिक कार्यों की भी चर्चा की।

श्री होसबाले ने प्रो. बाल आप्टे के जीवन के अनेक पक्षों की चर्चा करते हुए कहा कि मनुष्य के अंदर आलस, अहंकार, नफरत और स्वार्थ जैसे प्रदूषण को भी ठीक करने की जरूरत है क्योंकि अगर पर्यावरण को बदलने की बात है तो मनुष्य को भी अपनी जीवन शैली में बदलाव करने की जरूरत है। उन्होंने एक

▶ समग्रता का प्रतीक है समिधा: भूपेन्द्र यादव

अच्छे मित्र की आवश्यकता को बताते हुए कहा कि-

"पापान्निवारयति योजयते हिताय
गुह्यं निगुहति गुणान्प्रकटीकरोति ।
आपद्गतं च न जहाति ददाति काले
सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः।।"

अर्थात अच्छे मित्र के ये छः लक्षण बताएं हैं। ये छः लक्षण जिसके अंदर होते हैं। वही सही अर्थों में मित्र कहलाने के योग्य है- जो पापों से बचाए, पाप कर्म करने से बचाए और अच्छे कर्मों में लगा दे। छिपाने योग्य बातों को छुपाए और हमारे गुणों को समूह में प्रकट करे। आपत्तियां आने पर कभी साथ ना छोड़े और समय आने पर भरपूर सहयोग करें। संत लोग अच्छे मित्रों के यही लक्षण बताते हैं।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने डॉक्टर राकेश मिश्र को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपने विचारों को पुस्तक के रूप में प्रतिपादित किया है, जो बताता है कि डॉ. राकेश मिश्र की राजनीतिक समझ और सामाजिक उपलब्धियाँ बहुत बड़ी हैं। उन्होंने कहा कि समिधा का अर्थ है अग्नि को लकड़ी, सुगंधित पदार्थ इत्यादि समर्पित करना। आप्टेजी हमारे लिए बहुत आदर्श एवं श्रेष्ठ व्यक्ति थे। वह अपने समय के बहुत ही पाबंद व्यक्ति थे। भूपेन्द्र यादव ने कहा कि उनके साथ रहकर सीखने के लिए बहुत कुछ सीखा और यह वह व्यक्ति थे, जिन्होंने भाजपा को संवारने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि राकेश ने पुस्तक में पर्यावरण को लेकर भी चर्चा की है और आज के दौर में पर्यावरण अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने कई कदम उठाए हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर बनाया जिसका मुख्यालय गुड़गांव में है। इसमें 137 देश सहभागी हैं। हम एक पेड़ लगाकर धरती द्वारा जो जीवन हमें दिया गया है उसको हम थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर सकते हैं। प्रकृति के प्रति हमारा कुछ कृतज्ञता है और उसी श्रंखला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान चलाया उसके माध्यम से आज 140 करोड़ पेड़ पूरे देश भर में लगाये गए हैं।

पुस्तक के लेखक डॉ. राकेश मिश्र ने कहा कि इस पुस्तक में राष्ट्रवादी विचारधारा के चिंतकों के व्यक्तित्व और कृतित्व को संकलित किया गया है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुकर्जी, महान राष्ट्रवादी चिंतक पं. दीनदयाल उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, प्रो. बाल आप्टे, मदन दास देवी एवं गोपालजी व्यास के व्यक्तित्व पर केन्द्रित आलेख हैं। भगवान परशुराम, भगवान धन्वंतरि एवं महात्मा बुद्ध का स्मरण किया है। लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद किया है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कार्यों एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान में देश के कुशल गृहमंत्री अमित शाह जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को भी आलेख के माध्यम से रेखांकित कराने का प्रयास किया है।

छात्रशक्ति, युवाशक्ति एवं नारी शक्ति की महत्ता, योग एवं पर्यावरण के महत्व, देवभाषा संस्कृत और राष्ट्रभाषा हिन्दी को लेकर आलेख इस पुस्तक में संकलित है। इस अवसर अपने तपस्वी पूज्य पिता पं. गणेश प्रसाद मिश्र (दद्दाजी) एवं माता श्रीमती शांति मिश्रा जी को याद करते हुए भावुक होते हुए डॉ. राकेश मिश्र ने कहा कि उन्हीं से मिले आशीर्वाद से मिले संबल से यह कार्य सम्पन्न हो सका है। एडवोकेट संकल्प मिश्र ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ध्यन्यवाद ज्ञापित किया।

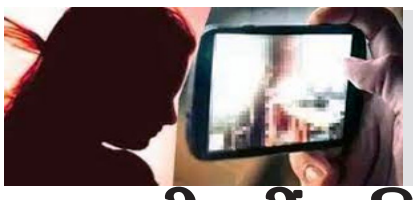

हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ स्क्रीन पर दिखना असल में जीने से ज्यादा जरूरी हो गया है। जहां ज़िंदगी कैमरे के फ्रेम में सिमट गई है, और इंसान का मूल्य उसके 'लाइक', 'फॉलोवर' और 'व्यूज' से तय होता है। इसी डिजिटल होड़ में स्त्रियों की अभिव्यक्ति भी एक अजीब मोड़ पर आ खड़ी हुई है – जहां रील बनाना कोई बुरा काम नहीं, लेकिन रील के बहाने स्त्री की गरिमा और उसकी सामाजिक छवि का बेशर्म चीरहरण किया जा रहा है।

बदन की नहीं, बुद्धि की बनाओ पहचान बहनों: अश्लीलता की रील संस्कृति पर एक सवाल

जिम, मॉल, सड़क, बाथरूम और बेडरूम–हर कोना अब कंटेंट स्टूडियो बन चुका है। कुछ लड़कियाँ सोशल मीडिया पर जिस तरह की अश्लील और भद्दी रील्स बना रही हैं, वह केवल खुद की नहीं, समूची नारी जाति की गरिमा पर धब्बा बन रही है। क्या आपको सच में लगता है कि महज ₹वायरल₹ हो जाने से कोई ताकतवर बनता है?

एक औरत के पास उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका आत्मसम्मान और विवेक होता है। आज जो लड़कियाँ एक्सरसाइज के नाम पर ऐसे कपड़े पहन रही हैं कि देखना भी शर्मिंदगी पैदा करे, वे शायद यह नहीं जानतीं कि वे नारी मुक्ति नहीं बल्कि नारी बाजारीकरण का प्रचार कर रही हैं। शरीर दिखाकर पहचान बनाना कोई गर्व की बात नहीं। अगर रील्स ही बनानी हैं, तो क्यों न ऐसी रील बनाओ जिसमें आपकी कला, मेहनत, सोच और संवेदना झलके? आज हर तीसरी रील में पिछवाड़ा फ्रेम के बीच में है, कैमरा कमर पर जूम करता है, और कैप्शन होता है – क्लासी एंड सेक्सी! क्या यही स्त्री की परिभाषा बनती जा रही है?

स्त्री आंदोलन कभी इस उद्देश्य से नहीं चला था। हमने शिक्षा, समानता, आजादी और आत्मनिर्भरता की लड़ाई लड़ी थी, न कि मंच पर खड़े होकर अंग प्रदर्शन की। जो लोग कहते हैं, ₹ये स्त्रियों की आजादी है₹, उनसे पूछिए–क्या शरीर को उत्पाद बनाना आजादी है या आधुनिक गुलामी? और यह दोष सिर्फ उन लड़कियों का नहीं है जो ऐसी रील्स बनाती हैं। यह समाज का भी अपराध है–खासतौर पर पुरुषों का। यही पुरुष ऐसी वीडियो पर मिलियन-मिलियन व्यूज देते हैं, लाइक ठोकते हैं, फिर कमेंट में नैतिकता का भाषण भी पेलते हैं। एक ही वीडियो में पुरुष की आँखें भी डोलती हैं और उंगलियाँ भी नैतिकता टाइप करती हैं। यह दोगलापन बंद होना चाहिए।

सोचिए, क्या होगा जब कोई छोटी बच्ची यह सब देखकर बढ़ेगी? जब वह देखेगी कि ज्यादा अंग दिखाने वाली को ज्यादा लाइक मिलते हैं, तो वह किस दिशा में जाएगी? यह रील संस्कृति, स्त्रीत्व को छीनने की चुपचाप होती साजिश है। डिजिटल ग्लैमर की इस दौड़ में हम स्त्री को फिर से उस स्थान पर ले जा रहे हैं जहाँ उसे सिर्फ 'देखे जाने' की वस्तु बना दिया गया था। आजादी की सही परिभाषा वो होती है जिसमें स्त्री खुद के लिए जीती है, न कि समाज के क्लिकबाजी वाले बाजार के लिए। एक लड़की सुंदर हो सकती है, फैशनेबल भी, लेकिन क्या जरूरी है कि वह हर बार अपनी देह को ही सेल करे? क्या सोच, क्या विचार, क्या चरित्र, क्या संघर्ष–ये सब सिर्फ उपन्यासों की बातें रह गई हैं? दूसरी तरफ, जिन प्लेटफॉर्म्स को समाजिक सुधार का औजार माना गया था–जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक–उन्हें हमने डिजिटल कोठा बना डाला है। यह केवल सरकार की असफलता नहीं है, बल्कि हम सब की चुप्पी का परिणाम है। यह लड़ाई सिर्फ महिलाओं की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की होनी चाहिए जो एक स्वस्थ, गरिमामय, और नैतिक समाज की कल्पना करता है। जो चाहता है कि उसकी बेटी, बहन, दोस्त या पत्नी डिजिटल दुनिया में अपने टैलेंट से पहचानी जाए, न कि अपनी कमर के घुमाव से।

अब समय आ गया है कि स्त्रियाँ खुद आगे बढ़कर कहें–बस बहुत हुआ। रील्स बनानी हैं, बनाओ, लेकिन सोच से बनाओ।

डांस करो, पर आत्मा से– कैमरे की भूख से।

हंसाओ, सुनाओ, सिखाओ, जोड़ो–क्योंकि स्त्री सिर्फ आकर्षण नहीं, प्रेरणा होती है।

और पुरुषों से भी यही कहना है–अब अपने क्लिक से समाज को मत चलाओ।

अगर अश्लीलता बंद करनी है, तो उसे देखना बंद करो। रील्स वायरल तब होती हैं जब उन्हें देखे जाने वाले आंख मूंद लेते हैं और दिल खोल देते हैं।

एक बात और–जो लड़कियाँ यह सोचती हैं कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं, वे ये समझें कि पसंद और उपभोग में फर्क होता है।

एक को देख कर सम्मान मिलता है, दूसरे को देख कर हवस जागती है। आप खुद तय करें, आप कौन सी नजरों में आना चाहती हैं? शायद अब वक्त है एक नई डिजिटल क्रांति का, जहाँ स्त्री के हाथ में मोबाइल हो–पर कैमरे के सामने न शरीर, बल्कि विचार हों।

रील में न खोओ बहना, सोच को आवाज दो,
जो तुम हो भीतर से, वही असली साज दो।
बदन की नहीं, बुद्धि की बनाओ पहचान,
यही है स्त्री की सबसे ऊँची उड़ान!

-प्रियंका सौरभ

घूँघट की बगावत

20 जुलाई 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

3

जैसी परवरिश वैसी आदतें बच्चा ऐसा जो बोलना नहीं भौंकना जानता

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हैं, यानि उसे समाज में रहने की आदत है और वो अकेला नहीं रह सकता। अगर उसे इंसानों के बजाय जानवरों में छोड़ा जाएगा, तो वो उनके जैसा ही बन जाएगा। इस बात का ताजा उदाहरण थाईलैंड से सामने आया है, जहां एक ऐसा बच्चा मिला है, जो बोलना ही नहीं जानता। बच्चे की उम्र 8 साल है लेकिन उसे ये नहीं पता है कि सामने वाले से बात कैसे करते हैं। दुनिया भर की सुर्खियों में छाए इस बच्चे की कहानी पहली बार छापी। बच्चा थाईलैंड के उट्टराडिट प्रांत का रहने वाला है। आपको एक ऐसी मां के बारे में बताएंगे, जिसने अपनी नशे की लत के चलते छोटे से बच्चे को कुत्तों के बीच मरने छोड़ दिया। हालांकि उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिसकी मां और बड़े भाई ने उसे दुत्कार दिया, उसे आवारा कुत्तों ने पाल लिया। बच्चों और महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्था पवीना होंगस-ाकुल को 8 साल का ये बच्चा रेड जोन में मिला, जहां ड्रग्स के शिकार लोग रहते हैं। उसकी मां और बड़े भाई नशे की लत से ग्रस्त हैं, ऐसे में बच्चे पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो ज्यादातर वक्त घर के पास रहने वाले कुत्तों के साथ ही रहने लगा। ऐसे में वो उनकी तरह की व्यवहार करता है और भौंककर ही अपनी बात कहता है। फाउंडेशन को इस बच्चे के सामने जिले के एक स्कूल की प्रिंसिपल ने रखा था, जिसके पास बच्चे की मां स्कूल का भत्ता लेने पहुंची थी, लेकिन बच्चे को स्कूल में एडमिट नहीं कराया। मां और भाई ने कभी भी बच्चे को न प्यार दिया न ही उसके प्रति कोई जिम्मेदारी निभाई। ऐसे में बच्चे को कुत्ते के झुंड से जब अटेंशन मिला, तो वो उनकी तरह रहने लगा। वो उनकी ही नकल करता था और उसी तरह भौंकने भी लगा। वैसे तो बच्चे की 46 साल की मां और 23 साल का भाई है, लेकिन वे दोनों उसकी परवरिश के बजाय अपने ड्रग्स की खुराक पर ज्यादा ध्यान देते थे। मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद पुलिस को पता चला कि उसकी मां खाने और ड्रग्स के पैसे के लिए भीख मांगती थी। आमतौर पर लोग उससे दूर रहते थे और कोई भी बच्चे के साथ खेलता भी नहीं था। ऐसे में भावनात्मक रूप से छूट चुके बच्चे ने कुत्तों के बीच शरण ले ली। फिलहाल उसे एक बाल गृह में भेजा गया है, जहां उसे सही तरह से बोलना और पढ़ना सिखाया जाएगा।

राज्य सरकार की स्टार्टअप शुरू करने की योजना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार हर जिले में 500 स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रही है, जो ओडीओपी की तर्ज पर स्थानीय पहचान और उत्पादों पर आधारित होंगे। पहले चरण में 35 हजार स्टार्टअप तैयार करने की योजना है, जिससे युवाओं को उनके जिले में ही रोजगार मिलेगा। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग इस मिशन को लागू करेगा, जिसमें इन्क्यूबेटर और फंडिंग से छोटे कारीगरों को वैश्विक मंच मिलेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को उनके जिले में ही रोजगार देने के लिए एक बड़ी योजना शुरू की है। हर जिले में 500 स्टार्टअप शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, जो एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की तरह स्थानीय विशेषताओं और पहचान पर आधारित होंगे। इस स्टार्टअप मिशन से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

यूपी सरकार का स्टार्टअप मिशन स्थानीय उत्पादों, जीआई टैग और जिले की औद्योगिक पहचान को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसके तहत छोटे कारीगरों और युवा उद्यमियों को वैश्विक मंच और वित्तीय सहायता दी जाएगी। उदाहरण के लिए, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर जैसे शहरों को आईटी और औद्योगिक केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। यह योजना नोएडा या ग्रेटर नोएडा जैसे बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि छोटे कस्बों तक पहुंचेगी। वर्तमान में, यूपी में करीब 15 हजार पंजीकृत स्टार्टअप हैं, जबकि गैर-सरकारी आंकड़ों में यह संख्या 27 हजार है। सरकार अब हर जिले में कम से कम एक इन्क्यूबेटर स्थापित करने की योजना बना रही है। वर्तमान में, 70 इन्क्यूबेटरों को सरकारी सहायता मिल रही है, लेकिन अब इसे सभी जिलों तक विस्तार दिया जाएगा। इन इन्क्यूबेटरों में स्टार्टअप विशेषज्ञों की टीमें होंगी, जो ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर युवा उद्यमियों को मार्गदर्शन देंगी।

यूपी स्टार्टअप नीति 2020 (संशोधन 2022) के तहत पहले ही 10 हजार स्टार्टअप्स का लक्ष्य रखा गया था। इस नीति में स्टार्टअप्स को कई तरह की सहायता दी जाती है। इसमें भारतीय पेटेंट के लिए 2 लाख और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए 10 लाख तक की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। सीड कैपिटल और मार्केटिंग के लिए 7.5 से 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। वहीं, महिलाओं, दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलता है। यूपी के आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा, ‘हमारा लक्ष्य युवाओं को उनके जिले में ही रोजगार उपलब्ध कराना और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना है।’ यह मिशन छोटे कारीगरों, जैसे हस्तशिल्प या जीआई टैग वाले उत्पाद बनाने वालों को स्टार्टअप के जरिए फंडिंग और बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगा। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि यूपी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। यह स्टार्टअप मिशन उत्तर प्रदेश को नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देगा।

डराने वाली चेतावनी समुद्र के पानी में नमक का बढ़ना

समुद्र पृथ्वी पर सबसे बड़ा जलस्रोत है. धरती की सतह का लगभग 71 प्रतिशत हिस्सा समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है, लेकिन इतना सारा पानी होने के बाद भी उसे हम पी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पानी बहुत खारा होता है। इसमें नमक की बहुत मात्रा होती है। हाल ही में एक नई स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि समुद्र के पानी में नमक की मात्रा बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों ने बढ़ते खारेपन को गंभीर चिंता का विषय बताया है, वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्री जल में लवण की मात्रा बढ़ रही है और अंटार्कटिका में इस तरह से पानी में नमक की मात्रा का बढ़ना खतरनाक है और असामान्य चेतावनी भी है. साइंटिस्ट ने कहा है कि गहरे समुद्र में कुछ बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में समुद्री धाराएं, बर्फ का पिघलना और मौसम सबकुछ आपस में जुड़ा हुआ है और इंसानी जरूरतों, समुद्री जीवन पर असर डाल रहा है। इस स्टडी में यूरोप के कई देशों के वैज्ञानिक शामिल थे। ऐसे में पानी में नमक की मात्रा को 2011 से 2023 तक यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट के जरिए मापा गया था। वैज्ञानिकों ने जब इसके बारे में स्टडी की तो बर्फ के घटने और पानी में नमक की मात्रा के बढ़ने का सीधा लिंक था। सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली गईं थीं, उनसे पता चला कि अंटार्कटिका के चारों तरफ के समुद्र का पानी ज्यादा खारा हो चुका है।

हर-हर महादेव के जयकारे से गूंज उठा पंचमुखी शिव मंदिर

महाजगंज, ठूठीबारी। सावन माह के पहले सोमवार को मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध पंचमुखी शिव मंदिर इटहिया में भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान हर हर महादेव, बोल बम के जयकारे से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। ठूठीबारी कोतवाली क्षेत्र के ईटहिया स्थित पंचमुखी भगवान भोलेनाथ के मंदिर परिसर में सावन भर मेला लगता है। सावन माह के पहले सोमवार पर बाबा भोलेनाथ को जल चढाने के लिए पड़ोसी देश नेपाल समेत भारतीय क्षेत्र के महराजगंज, फरेंदा, नौतनवा, सोनौली, बरगदवां, डगरुपुर, ठूठीबारी, निचलौल, सिसवा, घुघली, मिठौरा, सिंदुरियां, भटहट, परतावल, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर समेत बिहार राज्य से रविवार को ही शिव भक्तों की टोली के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। मंदिर के पुजारी ध्यान गिरी ने बताया कि सोमवार की भोर से ही पंचमुखी बाबा भोले नाथ को जल चढना प्रारंभ हुआ। इस दौरान इटहियां शिव मंदिर पहुंचे शिव भक्तों ने भगवान शंकर को बेलपत्र, भांग, धतूरा, पुष्प,अक्षत, जल चढ़ाकर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की।

बारिश से किसानों के चेहरे खिले

गोखपुर/औराताल। बारिश का इंतजार करते-करते अधिकतर किसानों ने सिंचाई के साधनों से पानी चला कर रोपाई कर दी। लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जो बारिश के सहारे थे। बीते सोमवार को सावन की पहली बारिश ने उनके उन किसानों को खुश कर दिया। धनपाल निषाद ने बताया धान की रोपाई किए 15 दिन हो गए। फसल सूख रही थी। लेकिन बारिश ने हरा भरा कर दिया। फौजदार ने बताया कि ,सुबह से बादल छाए थे। कई बार बादल आकर कर चले गए इस बार उम्मीद नहीं टूटी। जमकर बारिश हुई। जो किसान धान की सफाई कर चुके थे, उन्होंने तो फायदा हुआ है,जो लोग बारिश न होने के कारण रोपाई नहीं किए थे, सिंचाई के साधन वहां पर नहीं थे। उन किसानों को भी लाभ मिला है।

पिंक बूथ पर होगा पारिवारिक मामलों का निपटारा

बखिरा। पारिवारिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए शासन के आदेश पर सर्किल स्तर पर बखिरा थाना परिसर में पिंक बूथ बनाया गया है। मेंहदावल सर्किल के धर्मसिंहवा, बेलहर, मेंहदावल और बखिरा थाना क्षेत्र के पारिवारिक विवादों के निपटारा पिंक बूथ पर होगा। यहां आकर पीड़ित पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श भी ले सकते हैं।

पिंक बूथ प्रभारी शिखा गुप्ता ने बताया मिशन शक्ति अभियान के तहत परिवार परामर्श (काउंसिलिंग) के लिए सर्किल स्तर पर परिवार परामर्श केंद्र स्थापित किया गया है। मेंहदावल सर्किल क्षेत्र की महिलाओं को अब अपनी शिकायतों के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। धर्मसिंहवा, मेंहदावल, बेलहर व बखिरा क्षेत्र के लोग थाना बखिरा में आकर पारिवारिक समस्या समाधान के लिए परामर्श ले सकते हैं। परामर्श केंद्र के माध्यम से अधिकांश परिवार टूटने से बच जाते हैं।

उन्होंने बताया कि पिंक बूथों के माध्यम से पति-पत्नी और पारिवारिक विवाद या मतभेद के प्रकरण में मध्यस्थता कर उनका सम्यक निराकरण कराया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य थाने में आने वाली पारिवारिक विवाद संबंधी शिकायतों में कमी लाना, विवाद से ग्रस्त व्यक्ति व परिवारों को बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना व दोनों पक्षों को क-ांउसलर उपलब्ध कराना है। महिला कर्मियों की ओर से पिंक बूथ पर महिलाओं की समस्याओं को सुनकर निस्तारण करने से महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत होगी, तभी पिंक बूथ का उद्देश्य भी सार्थक होगा।

शिक्षकों ने प्रार्थना सभा में बच्चों को गीता के श्लोक पढ़ाने का किया विरोध, निदेशक को लिखा पत्र

देहरादून। शिक्षकों ने प्रार्थना सभा में बच्चों को गीता के श्लोक पढ़ाने का विरोध किया है। एससी, एसटी शिक्षक एसोसिएशन ने इस मामले में शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि यह धार्मिक ग्रंथ है। संविधान के मुताबिक शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती।

शिक्षक एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार टम्टा ने कहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28(1) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पूर्णतः या आंशिक रूप से सरकारी निधि से संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। यह व्यवस्था देश की धर्मनिरपेक्षता और सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान की भावना को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। प्रार्थना सभा में गीता के श्लोक बढ़ाए जाने का निर्देश संविधान में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन करता है। जो सरकारी स्कूलों में धर्म निरपेक्ष शिक्षा के सिद्धांत को कमजोर करता है। सरकारी स्कूलों में विभिन्न धर्मों, जातियों और समुदायों के छात्र अध्ययनरत हैं। किसी एक धार्मिक ग्रंथ के श्लोकों को अनिवार्य रूप से लागू करना अन्य धर्मावलंबियों और समुदायों के बीच असहजता एवं भेदभाव की भावना को जन्म दे सकता है, जो सामाजिक समरसता और समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों के विपरीत है। एससी-एसटी शिक्षक एसोसिएशन, इस निर्देश का पुरजोर विरोध करता है। इस तरह के निर्देश को वापस लिया जाना चाहिए। एसोसिएशन का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समावेशी मूल्यों को बढ़ावा देना है, न कि किसी विशेष धार्मिक ग्रंथ को प्रोत्साहित करना।

खाद की कालाबाजारी पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान

- यह विशेष अभियान 31 जुलाई तक चलाया जाएगा।
- अधिकारी प्रतिदिन करेंगे कृषि दुकानों का निरीक्षण
- अनियमितता पाए जाने पर हो तत्काल कार्यवाही

महराजगंज। जिले में खाद की कालाबाजारी और ओवर रेटिंग पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने सख्त कदम उठाया है। इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिसमें जिले की चारों तहसीलों सदर, फरेंदा, निचलौल और नौतनवा के उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, खंड विकास अधिकारी और थानाध्यक्ष शामिल हैं। यह विशेष अभियान 31 जुलाई तक चलाया जाएगा।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित अधिकारी प्रतिदिन अपने क्षेत्रों में कृषि दुकानों का निरीक्षण करेंगे और यूरिया खाद के स्टॉक, बिक्री दर और वितरण की स्थिति की जांच करेंगे। यदि कहीं अनियमितता या लापरवाही पाई गई तो तत्काल कार-ंवाई की जाएगी। खास तौर पर नेपाल सीमा से सटे नौतनवा और निचलौल तहसील क्षेत्रों में विशेष सख्ती बरती जाएगी, क्योंकि इन क्षेत्रों में यूरिया की तस्करी की आशंका अधिक रहती है। निचलौल तहसील के लिए जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि नौतनवा तहसील के लिए उप कृषि निदेशक संजीव कुमार को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोनों नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिदिन दुकानों की जांच करें और इसकी विस्तृत रिपोर्ट रोजाना प्रस्तुत करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का उद्देश्य किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराना और कालाबाजारी पर पूरी तरह रोक लगाना है। इस अभियान के तहत अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि खाद का वितरण पारदर्शी तरीके से हो और किसी भी दुकानदार की ओर से स्टॉक छिपाने या अधिक कीमत वसूलने की शिकायत न मिले। जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में यूरिया खाद की कालाबाजारी और ओवर रेटिंग पर लगाम लगाने के लिए जिलाधिकारी ने चारों तहसील क्षेत्रों में विशेष टीम बनाई गई है जो अपने क्षेत्रों में प्रतिदिन कृषि की दुकानों का निरीक्षण करेंगे। लापरवाही मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश हैं।

लिट्रेचर चयन में अंग्रेजी का लहराया परचम, हिंदी पीछे

छात्रों में दिखी अंग्रेजी विषय के प्रति विशेष रुचि

महराजगंज। स्नातक में प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज में इन दिनों गतिमान है। कला संवर्ग में विषय चयन में पहले की अपेक्षा इस बार बदलाव देखने को मिल रहा। डॉ. आंबेडकर राजकीय महाविद्यालय धनेवा-धनेई में कला संवर्ग में राजनीति शास्त्र प्रवेश लेने वालों की पहली पसंद है, जबकि पहले समाजशास्त्र के प्रति अधिक रुझान होता था। इसके अलावा प्राचीन इतिहास के प्रति भी रुचि देखी जा रही है।

इसके पीछे कारण जानने का प्रयास करें तो अब सिर्फ उत्तीर्ण होने के लिए विषय चयन विद्यार्थी नहीं कर रहे, बल्कि विषय में क्या भविष्य है इसपर भी फोकस कर रहे हैं। लिट्रेचर चयन में हिंदी की जगह अंग्रेजी का दबदबा इस बार देखा जा रहा है।

स्नातक पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया प्रभावी है। इस बार प्रवेश से पहले पंजीकरण प्रक्रिया अनिवार्य की गई थी। 30 जून तक समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराने के उपरांत ही प्रवेश की शर्त ने प्रवेश लेने की प्रक्रिया धीमी कर रखी है। बावजूद डॉ. आंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया तेज बनी हुई है। यहां स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान व व्यवसायिक वर्ग की 320 सीटों की दर से 960 सीट तय है, जिनमें से 513 सीटों पर प्रवेश पूर्ण हो चुका है।

वाणिज्य व विज्ञान के पाठ्यक्रम तो लगभग तय हैन, लेकिन कला वर्ग में जहां पहले ऐसे विषय चुनने का चलन था जिसमें अतिरिक्त श्रम करने की जरूरत न हो, लेकिन इस वर्ष विषय चयन में बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले लिट्रेचर पर हिंदी पसंदीदा था, लेकिन इस बार कला संवर्ग में हुए 180 प्रवेश में 130 ने लिट्रेचर अंग्रेजी चयन किया है।

50 की संख्या में ही विद्यार्थियों ने हिंदी का चयन किया है। 70 विद्यार्थियों ने राजनीति शास्त्र विषय चयन किया है, लेकिन समाजशास्त्र सिर्फ 35 ने ही चयनित किया। प्राचीन इतिहास को 43 ने पसंद किया है, जबकि भूगोल को 23 ने तवज्जो दिया है। कला संवर्ग में अभी 140 सीटों पर प्रवेश होना है। वहीं विज्ञान व व्यावसायिक में किसी विशेष परिवर्तन की स्थिति नहीं देखी जा रही।

डॉ. अमित कुमार गौड़, प्राचार्य, डॉ. भीमराव आंबेडकर राजकीय महाविद्यालय के अुसार पिछली बार की तुलना में इस बार पंजीकरण के बाद प्रवेश देने का नियम प्रभावी होने के कारण प्रवेश लेने की रफ्तार सुस्त है। फिर भी हमारे यहां की स्थिति प्रवेश में अन्य की तुलना में ठीक है। कला संवर्ग में अबतक हुए प्रवेश के मुताबिक लिट्रेचर में अंग्रेजी के साथ राजनीति शास्त्र व प्राचीन इतिहास की डिमांड अधिक है।

बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहा अस्पताल

पडरौना। महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा व इलाज मुहैया कराने के लिए शासन की ओर से तरह-तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। खासतौर पर गर्भवतियों पर उनका खास ध्यान है। लेकिन जिले में इन योजनाओं का असर नहीं नजर आ रहा है। 100 बेड के एमसीएच विंग (महिला अस्पताल) में लगी लिफ्ट खराब है। गर्भवतियों को पहली मंजिल पर जाने के लिए 22 सीढ़ियां चढ़नी पड़ रही है। अस्पताल में ड्रेनेज की व्यवस्था भी न होने से अस्पताल से निकलने वाला गंदा पानी परिसर में भर जा रहा है, जिससे मरीजों खास तौर पर गर्भवतियों को गंदे पानी और कीचड़ से होकर इलाज के लिए अंदर जाना पड़ रहा है। महिलाओं व नवजात शिशुओं का इलाज बेहतर हो सके, इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020 में जिले स्तर जिला अस्पताल परिसर में एमसीएच विंग (महिला अस्पताल) का शुभारंभ हुआ था। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में प्रतिदिन 200 से अधिक गर्भवतियां इलाज के लिए आती हैं। अगर उन्हें प्रसव पीड़ा है तो पहले, दूसरे और तीसरे महले पर भर्ती किया जाता है। वहीं, चौथी मंजिल पर 12 बेड का आईसीयू बनाया गया है, जहां गंभीर रोगियों को भर्ती कर इलाज किया जाता है। इन मरीजों में ब्रेन हेमरेज, ब्लड कैंसर, ब्रेन ट्यूमर के अलावा गंभीर बीमारियों से जुड़े मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जाता है। लिफ्ट खराब होने से एक तल पर जाने के लिए 22 सीढ़िया चढ़नी पड़ रही है। अगर चौथे महले पर जाना है तो 88 सीढ़ी चढ़नी होगी। मरीजों को खराब पानी से होकर परिसर में गुजरना पड़ रहा है। एंबुलेंस से जो गर्भवतियां आती हैं, उन्हें उतरकर अस्पताल में जाने में भी परेशानी होती है।

अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा यातायात नियमों का पाठ

संतकबीरनगर। परिषदीय स्कूलों में नामांकित छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए विद्यालयों की दीवारों पर यातायात के नियमों को अंकित किया जाएगा। विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों का पाठ पढ़ाया जाएगा। उन्हें इन नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। जिले में बेसिक शिक्षा परिषद से 1247 स्कूल संचालित हैं। इनमें करीब एक लाख छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। विद्यालय आने वाले बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। उन्हें यह संकल्प दिलाया जाएगा कि वे अपने अभिभावकों को इसके बारे में जागरूक करेंगे। विद्यालयों के छात्र रैली भी निकालेंगे। यातायात सप्ताह, यातायात पखवाड़ा और यातायात माह में स्कूलों के अंदर विभिन्न गतिविधियां और प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी। नए शैक्षिक सत्र में स्कूलों में यातायात के पुलिस कर्मी भी विद्यालय में जाकर उन्हें इसके बारे में जागरूक करेंगे। इसके पीछे उद्देश्य है कि भले ही इन विद्यालयों में छात्र बाइक न चलाते हो और सड़क पर कम निकलते हो, लेकिन इनकी शुरूआत से ही इसकी शिक्षा दी जाएगी तो वह जब तक बाइक व अन्य साधन का उपयोग करते समय इसकी बेहतर जानकारी होने से सावधानी बरतेंगे। साथ वह घर में अभिभावकों को भी जागरूक करेंगे।

बीएसए अमित कुमार सिंह ने बताया कि बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। स्कूल की दीवारों पर यातायात के नियम लिखवाए जाएंगे।

धर्मपरिवर्तन और दहेज उत्पीड़न के आरोपी परिजनों को मिली राहत

- कोर्ट ने मुकदमे की कार्यवाही पर लगाई अंतरिम रोक
- परिजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न-जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज
- कोर्ट ने कहा कि मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता
- राज्य और शिकायतकर्ता को एक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी में दिए गए उपहारों को आमतौर पर दहेज नहीं माना जाता। इस टिप्पणी संग कोर्ट ने जबरन धर्म परिवर्तन और दहेज उत्पीड़न के आरोपी परिजनों को राहत दे दी। साथ ही कोर्ट ने मुकदमे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी और कहा कि मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता है।

यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकलपीठ ने काशिफ अतहर व दो अन्य की याचिका पर दिया। गाजियाबाद निवासी फराज का एक दूसरे धर्म की युवती से प्रेम संबंध था। विवाह के पहले एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहीं, इसके कुछ दिनों बाद युवती ने आत्महत्या कर ली। इस पर युवती के पिता ने फराज, उसके भाई काशिफ अतहर, उसकी मां और बहन पर दहेज उत्पीड़न-जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया।

ट्रायल कोर्ट ने पुलिस के आरोप पत्र का संज्ञान लेकर समन आदेश जारी किया। काशिफ अतहर, उसकी मां और बहन ने दर्ज मुकदमे की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की। आवेदक के वकील ने दलील दी कि एफआईआर में आवेदकों के खिलाफ केवल इतना आरोप है कि उन्होंने एक होटल में विवाह के पहले समारोह में भाग लिया था।

जबरन धर्म परिवर्तन और अन्य आरोप मुख्य रूप से सह-अभियुक्त फराज पर लगाए गए हैं। आवेदकों के खिलाफ एफआईआर में कोई सीधा आरोप नहीं है। 28 दिसंबर 2024 को पुलिस जांच के दौरान मृतका की बहन और मां के बयान में जबरन धर्म परिवर्तन के प्रयास के आरोप लगाए गए। ये आरोप झूठे हैं और आवेदकों को केवल सह-अभियुक्त फराज के रिश्तेदार होने के कारण फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने अर्जी का विरोध किया।

दलील दी कि विवाह के पहले समारोह में दी गई राशि दहेज के रूप में मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता है। राज्य और शिकायतकर्ता को एक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई 27 अक्तूबर तक आवेदकों के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी। हालांकि, सह-अभियुक्त फराज के संबंध में मुकदमा कानून के अनुसार जारी रह सकता है।

घूँघट की बगावत

20 जुलाई 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

4

फाइलों में लटकी तबादला नीति: शिक्षक टकटकी लगाए बैठा है

मॉडल संस्कृति विद्यालयों और प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत चयनित स्कूलों में शिक्षक तैनाती हेतु जो परीक्षा हुई थी, उसके परिणाम बनकर तैयार हैं। लेकिन घोषणा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सामान्य तबादला नीति 2025 को अभी तक कैबिनेट की स्वीकृति नहीं मिली है। यहां यह प्रश्न अनिवार्य हो जाता है कि क्या परीक्षा करवाने से पहले यह सुनिश्चित नहीं किया गया था कि नीति बन चुकी है या उसके अनुमोदन की समयसीमा क्या होगी? यदि परीक्षा का परिणाम नीति पर टिका है, तो उसे पहले क्यों लिया गया? यह एक प्रशासनिक चूक है या राजनीतिक विलंब? परिणाम न घोषित करने का तर्क यह भी दिया जा रहा है कि वे सीलबंद लिफाफों में रखे गए हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा, ताकि कोई हस्तक्षेप संभव न हो। यह ह्लसीलबंद ईमानदारीह्व की परंपरा एक ओर दिखाती है कि विभाग पारदर्शिता का ढोंग कर रहा है और दूसरी ओर यह भी स्पष्ट करता है कि परिणामों के साथ कुछ न कुछ संभावित खेल से विभाग खुद भी डरता है। इस स्थिति को और अधिक हास्यास्पद बनाती है विभाग की दोहरी प्रवृत्ति - जब वह एसएमसी जैसी संरचना बनाकर एक महीने में ही भंग कर देता है। यही विभाग है जो दिसंबर से तबादले करवाने की बात कर रहा है और जुलाई तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। हर सप्ताह एक नया आदेश आता है और अगले सप्ताह कोई दूसरा अधिकारी उसे रद्द करा देता है। इससे यह साफ हो जाता है कि विभाग में समन्वय का सर्वथा अभाव है। हर कोई अपने स्तर पर ह्लफैसलाह्व लेने को तत्पर है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को दिशा देने वाला कोई नहीं। शिक्षक वर्ग इस भ्रम और अपारदर्शिता से मानसिक थकावट का शिकार हो चुका है। हर विद्यालय में इसी एक मुद्दे पर बातचीत होती है झ कोई ट्रांसफर की फाइल बनवा रहा है, कोई उउछ फॉर्म भरवा रहा है, कोई रिजल्ट आने की प्रतीक्षा में है, और कोई अपने संपर्कों से जानकारी जुटाने की कोशिश में है। एक प्रकार का मानसिक खिंचाव और अस्थिरता है जो शिक्षकों के काम को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में यह सोचने योग्य है कि जिस व्यवस्था पर भविष्य की पीढ़ी टिकी है, वह खुद अस्थिर और भ्रामक हो गई है। इसके पीछे प्रशासन की निर्णयहीनता तो है ही, साथ ही यह राजनीतिक प्राथमिकताओं की भी उपेक्षा है। चुनावों, घोषणाओं, और दिखावटी योजनाओं में सरकारें व्यस्त हैं लेकिन शिक्षक तबादला नीति जैसी बुनियादी जरूरतों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। जब शिक्षक मानसिक रूप से अस्थिर रहेंगे, तो बच्चों की पढ़ाई कैसे स्थिर रह पाएगी? हरियाणा के कई जिलों में एक ही शिक्षक दो-दो स्कूलों में पढ़ा रहा है, कुछ स्कूलों में विषय विशेषज्ञ ही नहीं हैं, और दूसरी ओर जिनका तबादला होना चाहिए, वे वर्षों से एक ही स्थान पर टिके हैं। एमआईएस (मैनजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम) को आधार बनाकर ऑनलाइन तबादला प्रणाली की बात की गई थी। पर नीति न बनने के कारण यह सिस्टम भी अपडेट नहीं हो पा रहा। तकनीक का नाम लेकर प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने का दावा तो किया गया, लेकिन जब तक नीति नहीं आती, तब तक सब कुछ एक क्लिक से दूर है। यह एक ऐसा डिजिटल सपना है जो अभी तक साकार नहीं हुआ। शिक्षकों का प्रमोशन हुआ, कई स्थान रिक्त हो गए। अब सवाल यह है कि क्या ट्रांसफर प्रमोशन के बाद होंगे? अगर हां, तो फिर कितने और प्रमोशन लंबित हैं? इन सवालों का कोई जवाब विभागीय वेबसाइट पर नहीं है, केवल शिक्षक संगठनों के व्हाट्सएप ग्रुप में अफवाहें हैं। यही नहीं, विभाग के ही एक अधिकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक अगस्त में प्रस्तावित है। इसका मतलब है कि नीति अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आएगी, तब तक तो सत्र का मध्य आ जाएगा। और फिर यही तर्क दिया जाएगा कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए तबादले अगले सत्र तक स्थगित किए जाएं। यह चक्र हर साल दोहराया जाता है। नीति नहीं बनती, फिर कहा जाता है सत्र बीच में है। शिक्षक अपनी योजना नहीं बना पाते। न वे उउछ ले सकते हैं, न मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं कि उन्हें स्थानांतरण मिलेगा या नहीं। विभाग एक गंभीर संकट में है - जहाँ फाइलें चल रही हैं पर निर्णय नहीं। इस असमंजस का सबसे बड़ा नुकसान विद्यार्थी झेलते हैं। जब कोई शिक्षक दो साल से ट्रांसफर की प्रतीक्षा में है, तो उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से पढ़ाई से हटता है। कई शिक्षक ऐसे हैं जो घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर कार्यरत हैं और पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के कारण मन से अशांत हैं। क्या यही मानसिकता लेकर वे बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे? यह भी सत्य है कि हरियाणा में तबादलों के नाम पर वर्षों से राजनीति हुई है। कभी ट्रांसफर लिस्ट में भाई-भतीजावाद होता है, कभी पंचायत चुनावों से पहले तबादले रुक जाते हैं, कभी किसी नेता के कहने पर नाम जोड़ या घटा दिए जाते हैं। पारदर्शिता की बात केवल नीति पत्रों में होती है, जमीन पर उसका कोई संकेत नहीं मिलता। यदि सरकार और विभाग वास्तव में शिक्षा सुधार को गंभीरता से लेना चाहते हैं, तो उन्हें इस स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले - स्पष्ट समयसीमा दी जाए कि तबादला नीति कब आएगी। दूसरा- जब तक नीति नहीं आती, तब तक परीक्षा परिणामों को लेकर भ्रम न फैलाया जाए। तीसरा - विभागीय समन्वय बढ़ाया जाए ताकि एक आदेश आने के बाद कोई दूसरा अधिकारी उसे रद्द न कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण हर प्रक्रिया को ऑनलाइन ट्रैक करने योग्य बनाया जाए। ट्रांसफर कोई कृपा नहीं, यह शिक्षक का अधिकार है। उसे फेवर की तरह प्रस्तुत करना, एक अपमानजनक प्रवृत्ति है। शिक्षक न तो कोई राजनैतिक कार्यकर्ता हैं, न ही किसी गुट का हिस्सा। वे उस नींव के पत्थर हैं, जिन पर समाज का भविष्य खड़ा है। और यदि नींव को ही अनिश्चितता में रखा जाएगा, तो शिखर कैसे मजबूत बनेगा?

चुनावों, घोषणाओं, और दिखावटी योजनाओं में सरकारें व्यस्त हैं लेकिन शिक्षक तबादला नीति जैसी बुनियादी जरूरतों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। जब शिक्षक मानसिक रूप से अस्थिर रहेंगे, तो बच्चों की पढ़ाई कैसे स्थिर रह पाएगी? हरियाणा के कई जिलों में एक ही शिक्षक दो-दो स्कूलों में पढ़ा रहा है, कुछ स्कूलों में विषय विशेषज्ञ ही नहीं हैं, और दूसरी ओर जिनका तबादला होना चाहिए, वे वर्षों से एक ही स्थान पर टिके हैं।

मानव इतिहास की परिधि पर जब भी कोई नया चक्र उभरता है, तो उसमें विज्ञान, कल्पना और आत्मबल की त्रयी सबसे महत्वपूर्ण होती है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा, जो एक समय टिन के डब्बों में साइकिलों पर रॉकेट लेकर चलने से शुरू हुई थी, आज न केवल चंद्रमा और मंगल की मिट्टी तक पहुंच चुकी है, बल्कि मानव संसाधन के नए क्षितिज भी गढ़ रही है। हाल ही में संपन्न हुई भारतीय मूल की गगनयात्री सुनीता विलियम्स की ऐतिहासिक वापसी, न केवल अमेरिका की सफलता है, बल्कि भारत के अंतरिक्ष स्वप्नों को भी नए पंख दे गई है। उनके साहस ने भारत की आधी आबादी—नारी शक्ति—को यह संदेश दिया है कि अब अंतरिक्ष केवल विज्ञान का विषय नहीं, बल्कि आत्मबल, समानता और नवाचार का प्रतीक बन चुका है।

अंतरिक्ष में भारत की उड़ान : विज्ञान, साहस और आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा

भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम कोई दिखावा नहीं, बल्कि जमीनी जरूरतों का समाधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम की सटीक जानकारी, किसानों के लिए फसल पूवार्नुमान, आपदा प्रबंधन, संचार और शिक्षा के लिए सस्ती सेवाएं—ये सब हमारे उपग्रहों की देन हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सफलता सिर्फ रॉकेट प्रक्षेपणों की संख्या में नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता, सटीकता और न्यूनतम लागत में छुपी हुई है। यही कारण है कि दुनिया के बड़े राष्ट्र भी आज अपने उपग्रह प्रक्षेपण के लिए भारत का रुख कर रहे हैं।

चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग और आगामी ह्यगगनयानह्व मिशन भारत को उस गुट में खड़ा कर रहे हैं, जहाँ सिर्फ चंद विकसित देश अब तक मौजूद थे। गगनयान मिशन, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्वदेशी यान में अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि भारतीय आत्मगौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का प्रतीक होगा। इस यात्रा का सबसे रोचक पहलू यह है कि इसमें अब केवल वैज्ञानिक ही नहीं, आम भारतीय युवाओं के लिए भी संभावनाओं के नए द्वार खुल रहे हैं। इसरो, रक्षा अनुसंधान संगठन और निजी क्षेत्र के सहयोग से भारत एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रहा है जहाँ विज्ञान, नवाचार, रोजगार और उद्यमिता एक साथ फल-फूल सकते हैं।

सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, और अब भारत की युवा वैज्ञानिक—ये सब उदाहरण हैं उस शक्ति के जो अंतरिक्ष में भी ह्यसीमितह्व नहीं है। आज देश की बेटियाँ रोवर बना रही हैं, सॉफ्टवेयर कोड लिख रही हैं, रॉकेट डिजाइन कर रही हैं। भारतीय अंतरिक्ष केंद्रों में महिला वैज्ञानिकों की सक्रिय भागीदारी इस मिथक को तोड़ती है कि विज्ञान केवल पुरुषों का क्षेत्र है। यह केवल लैंगिक समानता की बात नहीं, यह सामाजिक न्याय और राष्ट्र निर्माण की नींव है। जब एक लड़की अंतरिक्ष में जाती है, तो पूरे समाज का सोचने का तरीका बदलता है।

देश के नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय विद्यालयों, सरकारी स्कूलों, और ग्रामीण अंचलों से आने वाले छात्र-छात्राएं अब स्पेस क्लब्स का हिस्सा हैं। नन्हे वैज्ञानिक अब मोबाइल एप्लिकेशन से रॉकेट लॉन्च की प्रक्रिया को समझ रहे हैं, और निजी स्टार्टअप्स जैसे 'अग्निकुल', 'स्काईरूट', और 'पिक्सेल' अंतरिक्ष आधारित स्टार्टअप संस्कृति को जन्म दे रहे हैं। यह परिवर्तन केवल पढ़ाई या परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजगार सृजन, नवाचार, और आर्थिक आत्मनिर्भरता की नींव भी है। अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सिर्फ सपना नहीं, योजनाबद्ध यथार्थ बनता जा रहा है।

भारत में 2021 में स्थापित हुए अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या 30 से बढ़कर 2025 में 190 से अधिक हो चुकी है। इस वृद्धि के पीछे न केवल सरकारी नीतियाँ हैं, बल्कि वह युवा ऊर्जा भी है जो रिस्क लेने को तैयार है। अब भारतीय युवा सिर्फ सरकारी नौकरी की तरफ नहीं देख रहा, वह अब सोचता है कि वह क्यों न खुद एक उपग्रह विकसित करे? क्यों न वह ह्यलॉन्च सर्विसह्व उपलब्ध कराए? क्यों न वह अंतरिक्ष कचरे की सफाई पर स्टार्टअप शुरू करे? यह वही ह्यनया भारतह्व है, जो न केवल ख्वाब देखता है, बल्कि उन्हें साकार भी करता है। भारत अब अंतरिक्ष विज्ञान में केवल एक अनुसरणकर्ता नहीं, एक पथप्रदर्शक बनता जा रहा है। अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका के कई देश भारत से सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। भारत द्वारा ह्यसार्क सैटेलाइटह्व का निर्माण यह दर्शाता है कि वह विज्ञान को केवल राष्ट्रहित में नहीं, विश्वहित में भी प्रयोग करना चाहता है। भारत की ह्यवसुधैव कुटुम्बकमह्व की भावना अब पृथ्वी तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह ब्रह्मांड तक विस्तार पा रही है।

हालांकि यह भी आवश्यक है कि अंतरिक्ष विज्ञान के इस उत्साह को तर्क और जिम्मेदारी के साथ देखा जाए। विज्ञान का उपयोग यदि केवल आत्मप्रशंसा या राजनीतिक प्रचार के लिए हो, तो वह अपने मूल उद्देश्य से भटक सकता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि अंतरिक्ष विज्ञान केवल चंद्रमा पर तिरंगा फहराने का उपक्रम नहीं, बल्कि गाँव-गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और आपदा राहत पहुंचाने का भी माध्यम है। सच्चा राष्ट्रवाद वही है जो विज्ञान को लोकमंगल से जोड़ता है, न कि केवल मीडिया तमाशा बनाता है।

भारत की अंतरिक्ष यात्रा केवल रॉकेटों की गिनती नहीं है। यह देश की चेतना, आत्मबल, नवाचार, और युवाशक्ति की उड़ान है। जब कोई बच्चा गाँव की मिट्टी से उठकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनने का सपना देखता है, जब कोई युवती कहती है कि वह सुनीता विलियम्स या कल्पना चावला बनना चाहती है, और जब कोई शिक्षक अपने छात्रों को ब्रह्मांड के रहस्यों से अवगत कराता है—तब समझिए कि भारत सचमुच उड़ रहा है। और यह उड़ान, केवल आकाश की ओर नहीं, एक समावेशी, स्वावलंबी और वैज्ञानिक समाज की ओर है। इसलिए, आइए हम विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं में सीमित न करें, उसे घर-घर तक पहुँचाएं। विज्ञान का दीपक केवल रॉकेट नहीं बनाता, वह आशा, समानता और आत्मनिर्भरता की लौ भी जलाता है। अंतरिक्ष में भारत की यह यात्रा यहीं नहीं थमेगी—यह हर उस हृदय की धड़कन बनेगी, जो सोचता है, जो गढ़ता है, और जो उड़ना चाहता है।

कांवड़ या हुड़दंग? आस्था की राह में अनुशासन की दरकार

कांवड़ यात्रा का स्वरूप अब आस्था से हटकर प्रदर्शन और उन्माद की ओर बढ़ गया है। तेज डीजे, बाइक स्टंट, ट्रैफिक जाम और हिंसा ने इसे बदनाम कर दिया है। इसके विपरीत रामदेवरा जैसी यात्राएं आज भी शांत, अनुशासित और समर्पित होती हैं। इसका कारण है भक्ति में विनम्रता, प्रशासनिक अनुशासन और राजनीतिक हस्तक्षेप की कमी। अब जरूरत है कि भक्ति को भक्ति ही रहने दिया जाए – अनुशासन के साथ, समर्पण के साथ, और समाज के प्रति ज़िम्मेदारी के साथ।

भारत जैसे धर्मप्रधान देश में तीर्थयात्राओं और धार्मिक यात्राओं का एक गहरा सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रहा है। इन यात्राओं का उद्देश्य आत्मशुद्धि, समर्पण और शांति की प्राप्ति होता है। परंतु हाल के वर्षों में कुछ तीर्थ यात्राएँ, विशेषकर कांवड़ यात्रा, अपने मूल स्वरूप से भटक कर हंगामा, शोर-शराबा और अनुशासनहीनता का पर्याय बनती जा रही हैं।

जहाँ एक ओर लाखों श्रद्धालु राजस्थान के रामदेवरा जैसे स्थानों पर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर शांति और श्रद्धा से पूजा-अर्चना करते हैं, वहीं दूसरी ओर कांवड़ यात्रा के दौरान अक्सर सड़कों पर कब्जा, डीजे की धुनों पर नाचना, ट्रैफिक जाम, तोड़फोड़ और मारपीट की खबरें आती रहती हैं। सवाल उठता है – क्या आस्था का मतलब अराजकता है? कांवड़िये ही हुड़दंग क्यों करते हैं, जबकि अन्य तीर्थयात्राएँ शांति से होती हैं?

श्रद्धा का स्वरूप: विनम्रता या प्रदर्शन?

भारत में धार्मिक यात्राओं का इतिहास पुराना है – पदयात्रा, व्रत, नियम और तपस्या इनका मूल हिस्सा रहे हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा, खासकर उत्तर भारत के कुछ इलाकों में, अब एक शक्ति प्रदर्शन में बदलती जा रही है। श्रद्धालु अब भक्त कम, और ₹रौबदार शिवभक्त₹ ज्यादा नजर आते हैं। बाइक पर 10-15 लोग, डीजे बजाते ट्रक, और शोर-शराबे में हर-हर महादेव का नारा – यह सब आस्था से अधिक दिखावे और गुटबाजी का प्रतीक लगता है। इसके विपरीत रामदेवरा की यात्रा में न कोई सुरक्षा खतरा, न सरकारी तामझाम, फिर भी वहां अनुशासन और सेवा का वातावरण होता है। ऐसा क्यों?

मर्दानगी और हर-हर महादेव का नया संस्करण

कांवड़ यात्रा में आज जो हुड़दंग दिखाई देता है, वह भक्ति का नहीं, मर्दानगी का अवतार है। ₹हर-हर महादेव₹ जैसे पवित्र नारे को कई बार उग्रता और हिंसा के साथ जोड़ दिया गया है। यह माचो मर्दानगी का ऐसा संस्करण है जिसमें भक्त बाइक पर स्टंट करता है, तेज म्यूज़िक पर झूमता है और किसी ने कुछ कहा तो झगड़े पर उतर आता है। रामदेवरा में लोग अपने परिवार के साथ, बड़ों के आशीर्वाद के साथ जाते हैं। वहाँ शांति, सेवा और दर्शन ही उद्देश्य होता है, न कि सोशल मीडिया रील्स और तड़क-भड़क।

प्रशासनिक ढिलाई और राजनीतिक मजबूरी

प्रशासन के लिए कांवड़ यात्रा अब आस्था का नहीं, सिरदर्द का विषय बन गई है। रास्तों को बंद करना पड़ता है, जबरदस्ती स्कूल-कॉलेज की छुट्टियाँ करनी पड़ती हैं और पुलिस को कांवड़ियों को मना करने की हिम्मत नहीं होती। इसके पीछे एक बड़ा कारण है – राजनीतिक संरक्षण। कोई भी सरकार कांवड़ियों को नाराज नहीं करना चाहती, विशेषकर जब धार्मिक भावनाएं उबाल पर हों। नतीजा यह होता है कि कुछ असामाजिक तत्व इस ढील का फायदा उठाकर पूरे आयोजन को बदनाम कर देते हैं।

सोशल मीडिया: भक्ति या ब्रांडिंग?

आजकल कांवड़ यात्रा का एक और बड़ा आयाम है – सोशल मीडिया प्रमोशन। भक्त कम, इन्फ्लुएंसर ज्यादा हैं। कोई रील बना रहा है, कोई फेसबुक लाइव कर रहा है, कोई अपने ट्रक की सजावट दिखा रहा है। भक्ति अब कैमरे के सामने पोज करने की प्रक्रिया बन गई है। रामदेवरा जैसे स्थलों पर ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं दिखती। वहाँ लोग अपने मन और आत्मा से जुड़ते हैं, न कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से।

समूह की ताकत और मनोवैज्ञानिक भ्रम

कांवड़ यात्रा का एक बड़ा पहलू है – भीड़ की ताकत और समूह मनोविज्ञान। जब सैकड़ों-हजारों लोग एक साथ चलते हैं तो व्यक्ति की जिम्मेदारी गायब हो जाती है। कोई एक गलती करता है, और पूरी भीड़ प्रतिक्रिया में उग्र हो जाती है। रामदेवरा जैसी यात्राओं में लोग छोटे-छोटे समूहों में या व्यक्तिगत रूप से जाते हैं। वहाँ अनुशासन भी व्यक्तिगत होता है और उत्तरदायित्व भी।

आस्था और उन्माद में अंतर

कांवड़ यात्रा में जो देखा जा रहा है, वह भक्ति नहीं, उन्माद है। यह वह धर्म नहीं है जिसकी शिक्षा भगवान शिव देते हैं। वे तो योगी हैं, शांति और तपस्या के प्रतीक हैं। उन्हीं शिव के नाम पर सड़कें कब्जा करना, गाड़ियों में तोड़फोड़ करना, दुकानें बंद करवाना – यह कहां की भक्ति है? क्या यह ईश्वर को प्रसन्न करता है या समाज को संकट में डालता है?

समाधान: भक्ति में अनुशासन और प्रशासन में दृढ़ता

समस्या की पहचान जरूरी है, लेकिन समाधान भी उतना ही जरूरी है। इस दिशा में निम्नलिखित सुझाव कारगर हो सकते हैं: धार्मिक संगठनों को आगे आना चाहिए जो कांवड़ यात्रा का संयोजन करते हैं, उन्हें स्वयं अनुशासन और संयम का संदेश देना होगा। प्रशासन को राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर कानून का पालन करवाना चाहिए, चाहे वह कोई भी समुदाय हो। भक्तों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्या उनकी यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न कर रही है या बदनाम कर रही है। सोशल मीडिया पर फालतू दिखावे की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना चाहिए, और असामाजिक तत्वों की पहचान कर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

-प्रियंका सौरभ

परीक्षा प्रणाली या सामाजिक भ्रमजाल?

विजय गर्ग

शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला कहा गया है। यह व्यक्ति के ज्ञान, विवेक, सृजनात्मकता और व्यक्तित्व विकास का माध्यम रही है। लेकिन आज की तारीख में यह उद्देश्य कहीं पीछे छूट गया है। शिक्षा अब एक 'अंक- उद्योग' में तब्दील हो चुकी है, जहां ज्ञान की बजाय नंबर ही सफलता का पर्याय बन गए हैं। अब यह न तो चरित्र निर्माण का साधन रही, न ही सामाजिक चेतना का उपकरण। यह छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को अंक दौड़ की एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में धकेलने वाला शोषण तंत्र बन गई है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में इस बार 45,516 छात्रों ने 95 फीसदी से ज्यादा अंक प्राप्त किए, जो कुल परीक्षार्थियों का लगभग 1.92 प्रतिशत है। वहीं 1,99,944 छात्रों ने 90 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल किए, जो 8.43 प्रतिशत के करीब है। यह कोई अपवाद नहीं है हर साल यह आंकड़ा और ऊपर जा रहा है। लेकिन जब इन अंकों की असलियत जानने के लिए उत्तर पुस्तिकाएं जांचने वाले शिक्षकों की कार्यप्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली पर सवाल उठते हैं, तो व्यवस्था मौन हो जाती है। यह एक साजिशन खड़ा किया गया भ्रमजाल है, जो शिक्षा को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की बजाय एक कृत्रिम दौड़ में तब्दील कर रहा है।

शिक्षा के इस व्यवसायीकरण की गहराई को समझने के लिए जरूरी है कि हम उस ढांचे को देखें जिसमें यह सब संचालित हो रहा है। 2019 में सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कुल 22,030 स्कूलों में से लगभग 80 प्रतिशत स्कूल निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इस आंकड़े में केवल 1,138 केंद्रीय विद्यालय, 2,727 सरकारी स्कूल, 598 नवोदय विद्यालय और 14 तिब्बती स्कूल शामिल हैं, जबकि शेष 17,553 निजी स्कूल हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा निजीकरण के दबाव में है, जहां शिक्षा की गुणवत्ता नहीं, बल्कि परिणामों की संख्या मायने रखती है और जब यही 'अंकवीर' छात्र राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, जेईई या नीट में पहुंचते हैं, तो उनकी वास्तविक योग्यता सामने आ जाती है। उदाहरण के लिए, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 में लगभग 11.35 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से मात्र 11,474 छात्र ही मुख्य परीक्षा तक पहुंच सके। यही हाल साल 2024 का रहा। इस वर्ष लगभग 13.4 लाख छात्रों में से सिर्फ 14,627 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा तक पहुंचे। यानि बोर्ड परीक्षा के हाई स्कोरर प्रीलिम्स की पहली कसौटी पर ही फेल हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि बोर्ड परीक्षाओं में मिलने वाले ऊंचे अंक असल में बौद्धिक क्षमता या विषय की समझ का पैमाना नहीं हैं। यह मूल्यांकन प्रणाली रटंत विद्या तयशुदा उत्तरों और सजावटी भाषा पर आधारित है, जिसमें मौलिक सोच और विश्लेषण की कोई जगह नहीं।

उत्तर भारत के अधिकतर स्कूलों में शिक्षण अब गाइडबुक, मॉडल पेपर और स्मार्ट आंसर पर आधारित हो गया है। शिक्षक भी केवल परिणाम उन्मुख होकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके मूल्यांकन का आधार भी अब बच्चों के अंक बन गए हैं। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम बच्चों की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। नंबर की होड़ में बच्चों में अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति, हीन भावना और मानसिक तनाव बढ़ रहा है। शिक्षा अब ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि एक दौड़ बन गई है, जिसमें सबसे तेज दौड़ने वाला ही विजेता माना जाता है।

यह समस्या केवल स्कूली शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिकता पूरे उत्तर भारत के शैक्षणिक वातावरण में व्याप्त है। स्कूलों में अब शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान देना नहीं, बल्कि अच्छे परिणामों के जरिए स्कूल का नाम रौशन करना बन गया है। इसके उलट, दक्षिण भारत की तस्वीर अपेक्षाकृत बेहतर है। वहां के माता- पिता शिक्षा को केवल अंक पाने के माध्यम के रूप में नहीं, बल्कि व्यक्तित्व विकास और कौशल निर्माण के रूप में देखते हैं। यही कारण है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों के छात्र राष्ट्रीय परीक्षाओं में निरंतर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वहां की शिक्षा प्रणाली में केवल परीक्षाफल नहीं, बल्कि सोचने-समझने की क्षमता, व्यवहारिकता और नवाचार को भी महत्व दिया जाता है। उत्तर भारत के अधिकतर स्कूलों में शिक्षण अब गाइडबुक, मॉडल पेपर और स्मार्ट आंसर पर आधारित हो गया है। शिक्षक भी केवल परिणाम उन्मुख होकर पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके मूल्यांकन का आधार भी अब बच्चों के अंक बन गए हैं। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम बच्चों की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। नंबर की होड़ में बच्चों में अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति, हीन भावना और मानसिक तनाव बढ़ रहा है। शिक्षा अब ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि एक दौड़ बन गई है, जिसमें सबसे तेज दौड़ने वाला ही विजेता माना जाता है।

मलोट, पंजाब

फाइलों में लटकी तबादला नीति: शिक्षक टकटकी लगाए बैठा

हरियाणा के शिक्षक एक बार फिर से असमंजस, अफवाहों और अधूरी सूचनाओं के बीच फंसे हुए हैं। स्कूलों में रोज सुबह की शुरूआत चाय और स्टाफरूम की बातचीत से होती है झ्र ₹ट्रांसफर कब होंगे?₹ इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं, पर अनुमान सबके पास है। कोई कहता है अगस्त में, कोई कहता है कैबिनेट के बाद, कोई मानता है अब तो सत्र बीच में आ चुका है, इसलिए विभाग कुछ नहीं करेगा। सब कुछ ठहरा हुआ, धुंधला और अधर में लटका हुआ प्रतीत होता है।

मॉडल संस्कृति विद्यालयों और प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत चयनित स्कूलों में शिक्षक तैनाती हेतु जो परीक्षा हुई थी, उसके परिणाम बनकर तैयार हैं। लेकिन घोषणा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सामान्य तबादला नीति 2025 को अभी तक कैबिनेट की स्वीकृति नहीं मिली है।

यहां यह प्रश्न अनिवार्य हो जाता है कि क्या परीक्षा करवाने से पहले यह सुनिश्चित नहीं किया गया था कि नीति बन चुकी है या उसके अनुमोदन की समयसीमा क्या होगी? यदि परीक्षा का परिणाम नीति पर टिका है, तो उसे पहले क्यों लिया गया? यह एक प्रशासनिक चूक है या राजनीतिक विलंब?

परिणाम न घोषित करने का तर्क यह भी दिया जा रहा है कि वे सीलबंद लिफाफों में रखे गए हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा, ताकि कोई हस्तक्षेप संभव न हो। यह ह्लसीलबंद ईमानदारीह्व की परंपरा एक ओर दिखाती है कि विभाग पारदर्शिता का ढोंग कर रहा है और दूसरी ओर यह भी स्पष्ट करता है कि परिणामों के साथ कुछ न कुछ संभावित ह्यखेलह्व से विभाग खुद भी डरता है। इस स्थिति को और अधिक हास्यास्पद बनाती है विभाग की दोहरी प्रवृत्ति - जब वह SMC (School Management Committee) जैसी संरचना बनाकर एक महीने में ही भंग कर देता है। यही विभाग है जो दिसंबर से तबादले करवाने की बात कर रहा है और जुलाई तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। हर सप्ताह एक नया आदेश आता है और अगले सप्ताह कोई दूसरा अधिकारी उसे रद्द करा देता है। इससे यह साफ हो जाता है कि विभाग में समन्वय का सर्वथा अभाव है। हर कोई अपने स्तर पर फैसला लेने को तत्पर है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को दिशा देने वाला कोई नहीं।

शिक्षक वर्ग इस भ्रम और अपारदर्शिता से मानसिक थकावट का शिकार हो चुका है। हर विद्यालय में इसी एक मुद्दे पर बातचीत होती है झ्र कोई ट्रांसफर की फाइल बनवा रहा है, कोई उच्छ फॉर्म भरवा रहा है, कोई रिजल्ट आने की प्रतीक्षा में है, और कोई अपने संपर्कों से जानकारी जुटाने की कोशिश में है। एक प्रकार का मानसिक खिंचाव और अस्थिरता है जो शिक्षकों के काम को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में यह सोचने योग्य है कि जिस व्यवस्था पर भविष्य की पीढ़ी टिकी है, वह खुद अस्थिर और भ्रामक हो गई है।

शिक्षक वर्ग इस भ्रम और अपारदर्शिता से मानसिक थकावट का शिकार हो चुका है। हर विद्यालय में इसी एक मुद्दे पर बातचीत होती है झ्र कोई ट्रांसफर की फाइल बनवा रहा है, कोई उच्छ फॉर्म भरवा रहा है, कोई रिजल्ट आने की प्रतीक्षा में है, और कोई अपने संपर्कों से जानकारी जुटाने की कोशिश में है। एक प्रकार का मानसिक खिंचाव और अस्थिरता है जो शिक्षकों के काम को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में यह सोचने योग्य है कि जिस व्यवस्था पर भविष्य की पीढ़ी टिकी है, वह खुद अस्थिर और भ्रामक हो गई है।

इसके पीछे प्रशासन की निर्णयहीनता तो है ही, साथ ही यह राजनीतिक प्राथमिकताओं की भी उपेक्षा है। चुनावों, घोषणाओं, और दिखावटी योजनाओं में सरकारें व्यस्त हैं लेकिन शिक्षक तबादला नीति जैसी बुनियादी जरूरतों को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। जब शिक्षक मानसिक रूप से अस्थिर रहेंगे, तो बच्चों की पढ़ाई कैसे स्थिर रह पाएगी? हरियाणा के कई जिलों में एक ही शिक्षक दो-दो स्कूलों में पढ़ा रहा है, कुछ स्कूलों में विषय विशेषज्ञ ही नहीं हैं, और दूसरी ओर जिनका तबादला होना चाहिए, वे वर्षों से एक ही स्थान पर टिके हैं।

एमआईएस (मैनजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम) को आधार बनाकर ऑनलाइन तबादला प्रणाली की बात की गई थी। पर नीति न बनने के कारण यह सिस्टम भी अपडेट नहीं हो पा रहा। तकनीक का नाम लेकर प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने का दावा तो किया गया, लेकिन जब तक नीति नहीं आती, तब तक सब कुछ एक क्लिक से दूर है। यह एक ऐसा डिजिटल सपना है जो अभी तक साकार नहीं हुआ।

शिक्षकों का प्रमोशन हुआ, कई स्थान रिक्त हो गए। अब सवाल यह है कि क्या ट्रांसफर प्रमोशन के बाद होंगे? अगर हां, तो फिर कितने और प्रमोशन लंबित हैं? इन सवालों का कोई जवाब विभागीय वेबसाइट पर नहीं है, केवल शिक्षक संगठनों के व्हाट्सएप ग्रुप में अफवाहें हैं। यही नहीं, विभाग के ही एक अधिकारी के अनुसार कैबिनेट की बैठक अगस्त में प्रस्तावित है। इसका मतलब है कि नीति अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आएगी, तब तक तो सत्र का मध्य आ जाएगा। और फिर यही तर्क दिया जाएगा कि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए तबादले अगले सत्र तक स्थगित किए जाएं।

यह चक्र हर साल दोहराया जाता है। नीति नहीं बनती, फिर कहा जाता है सत्र बीच में है। शिक्षक अपनी योजना नहीं बना पाते। न वे उच्छ ले सकते हैं, न मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं कि उन्हें स्थानांतरण मिलेगा या नहीं। विभाग एक गंभीर संकट में है झ्र जहाँ फाइलें चल रही हैं पर निर्णय नहीं।

इस असमंजस का सबसे बड़ा नुकसान विद्यार्थी झेलते हैं। जब कोई शिक्षक दो साल से ट्रांसफर की प्रतीक्षा में है, तो उसका ध्यान स्वाभाविक रूप से पढ़ाई से हटता है।

कई शिक्षक ऐसे हैं जो घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर कार्यरत हैं और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण मन से अशांत हैं। क्या यही मानसिकता लेकर वे बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे?

यह भी सत्य है कि हरियाणा में तबादलों के नाम पर वर्षों से राजनीति हुई है। कभी ट्रांसफर लिस्ट में भाई-भतीजावाद होता है, कभी पंचायत चुनावों से पहले तबादले रुक जाते हैं, कभी किसी नेता के कहने पर नाम जोड़ या घटा दिए जाते हैं। पारदर्शिता की बात केवल नीति पत्रों में होती है, जमीन पर उसका कोई संकेत नहीं मिलता।

यदि सरकार और विभाग वास्तव में शिक्षा सुधार को गंभीरता से लेना चाहते हैं, तो उन्हें इस स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले झ्र स्पष्ट समयसीमा दी जाए कि तबादला नीति कब आएगी। दूसरा - जब तक नीति नहीं आती, तब तक परीक्षा परिणामों को लेकर भ्रम न फैलाया जाए। तीसरा - विभागीय समन्वय बढ़ाया जाए ताकि एक आदेश आने के बाद कोई दूसरा अधिकारी उसे रद्द न कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण हर प्रक्रिया को ऑनलाइन ट्रैक करने योग्य बनाया जाए।

ट्रांसफर कोई कृपा नहीं, यह शिक्षक का अधिकार है। उसे फेवर की तरह प्रस्तुत करना, एक अपमानजनक प्रवृत्ति है। शिक्षक न तो कोई राजनैतिक कार्यकर्ता हैं, न ही किसी गुट का हिस्सा। वे उस नींव के पत्थर हैं, जिन पर समाज का भविष्य खड़ा है। और यदि नींव को ही अनिश्चितता में रखा जाएगा, तो शिखर कैसे मजबूत बनेगा?

यह लेख एक आग्रह है झ्र शिक्षा विभाग और सरकार से, कि वह इस भ्रम, ढुलमुल रवैये और प्रशासनिक कायरता से बाहर आए। तबादला नीति को केवल फाइलों और लॉकरों में बंद करने के बजाय, जमीन पर उतारें। क्योंकि शिक्षक अब थक चुका है। और जब शिक्षक थकता है, तो पूरा समाज सुस्त हो जाता है।

डॉ. सत्यवान सौरभ

अति लालच के चलते मानव ने शुरु किया प्रकृति का शोषण

इस धरा पर जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव के लिए प्रकृति ने पर्याप्त खाद्य पदार्थ दिए हैं परंतु अति लालच के चलते मानव ने प्रकृति का शोषण करना शुरू कर दिया है। इसमें कोई अब कोई संदेह नहीं रह गया है कि मानव ने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए पर्यावरण का अत्यधिक नुकसान किया है और इसका परिणाम आज उसे ही भुगतना भी पड़ रहा है। कई देशों में तो भयंकर गर्मी में वहां के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं जिनसे जान और माल की भारी हानि हो रही है। हम पर्यावरण के सम्बंध में बढ़ चढ़ कर चर्चाएं तो करते हैं परंतु आज हमारे गावों में खेत, प्लाटों में परिवर्तित हो गए हैं। हमारे खेतों पर शोपिंग काम्प्लेक्स एवं मॉल खड़े हो गए हैं जिससे हरियाली लगातार कम होती जा रही है। बीते कुछ वर्षों में कंकरीट की इमारतों में अत्यधिक वृद्धि एवं भूमि प्रयोग में बदलाव के चलते भारत में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है। देश के महानगर अर्बन हीट आइलैंड बन रहे हैं। अर्बन हीट आइलैंड वह क्षेत्र होता है जहां अगल-बगल के इलाकों से अधिक तापमान रहता है। कई स्थानों पर अत्यधिक गर्मी के पीछे अपर्याप्त हरियाली, अधिक आबादी, घने बसे घर और इंसानी गतिविधियां जैसे गाडियों और गैजेट से निकलने वाली हीट आदि कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। कार्बन डाईआक्साइड और मेथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों एवं कूड़ा जलाने से भी गर्मी बढ़ती है। राजधानी दिल्ली का उदाहरण हमारे सामने है। जहां चारों दिशाओं में बने डंपिंग यार्डों में आग लगी ही रहती है और लोगों का सांस लेना भी अब दूभर हो रहा है। भारत ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो यानी कार्बन उत्सर्जन रहित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य तय किया हुआ है। यद्यपि पर्यावरण रक्षा में भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं लेकिन यह प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक देशवासी प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक अत्यधिक शोषण करना बंद नहीं करते। शहरों के बढ़ते तापमान की रोकथाम हेतु जरूरी है कि मौसम और वायु प्रवाह का ठीक तरह से नियोजन किया जाए। हरियाली का विस्तार, जल स्रोतों की सुरक्षा, वर्षा जल संचय, वाहनों एवं एयर कंडीशंस की संख्या की कमी से ही हम प्रचंड गर्मी को कम कर सकते हैं। पृथ्वी का तापमान घटेगा तभी मानव सुरक्षित रह पाएगा। उक्त संदर्भ में यह हम सभी भारतीयों के लिए हर्ष का विषय होना चाहिए कि हमारे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन मौजूद हैं जो सदैव ही सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सेवा कार्य करने वाले संगठनों को साथ लेकर, देश पर आने वाली किसी भी विपत्ति में आगे आकर, सेवा कार्य करना प्रारम्भ कर देते हैं। भारत के पर्यावरण में सुधार लाने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तो बाकायदा एक नई पर्यावरण गतिविधि को ही प्रारम्भ कर दिया है। जिसके अंतर्गत समाज में विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले संगठनों को साथ लेकर संघ द्वारा देश में प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल नहीं करने का अभियान प्रारम्भ किया गया है और देश में अधिक से अधिक पेड़ लगाने की मुहिम प्रारम्भ की गई है। साथ ही, विभिन्न शहरों को स्वच्छ एवं नशामुक्त बनाने हेतु भी विशेष अभियान प्रारम्भ किए हैं। उदाहरण के तौर पर ग्वालियर को स्वच्छ, नशामुक्त एवं प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का बीड़ा उठाया गया है। इसी संदर्भ में ग्वालियर महानगर में विविध संगठनों के दायित्ववान कार्यकताओं का दो दिवसीय शिविर आयोजित किया गया था। इस शिविर के एक विशेष सत्र में इस बात पर विचार किया गया कि ग्वालियर महानगर को स्वच्छ एवं नशामुक्त बनाया जाना चाहिए। उक्त शिविर के समापन के पश्चात उक्त समस्याओं के हल हेतु विविध संगठनों के दायित्ववान कार्यकताओं की तीन बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में विस्तार से विचार करने के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि कुछ चिन्हित कार्यकताओं को विभिन्न मठ, मंदिरों, स्कूलों, संस्थानों आदि में विषय प्रस्तुत करने हेतु भेजा जाए ताकि उक्त समस्याओं के हल में समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इस संदर्भ में चुने गए 60 कार्यकताओं के लिए एक वक्ता कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। इन चिन्हित कार्यकताओं को विभिन संस्थानों में विषय प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया था ताकि उक्त समस्याओं के हल करने हेतु समाज को भी साथ में लेकर कार्य को सम्पन्न किया जा सके।

तमिल फिल्म वेट्टुवम की शूटिंग के दौरान हुई स्टंटमैन एस एम राजू की मौत, शोकाकुल स्टंट बिरादरी

वह 13 जुलाई को नागपट्टिनम में निर्देशक पी रंजीत की फिल्म 'वेट्टुवम' के एक धमाकेदार स्टंट दृश्य के लिए एसयूवी चला रहे थे और अचानक बेहोश हो गए। उनके सहयोगियों ने उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

मुंबई/चेन्नई। स्टंट्स मैन राजू (52 वर्षीय) का असली नाम मोहन राज था। उनकी तमिलनाडु के नागपट्टिनम में एक फिल्म के एक्शन दृश्य की शूटिंग के दौरान मौत हो गई। वह 13 जुलाई को नागपट्टिनम में निर्देशक पी रंजीत की फिल्म 'वेट्टुवम' के एक धमाकेदार स्टंट दृश्य के लिए एसयूवी चला रहे थे और अचानक बेहोश हो गए। उनके सहयोगियों ने उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें सेट पर मौजूद लोगों को मोहन राज की मदद के लिए दौड़ते हुए और उन्हें कार से बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है।

बतातें चला जाए कि जाने-माने स्टंटमैन एस एम राजू की मौत पर स्टंट बिरादरी ने गहरा शोक व्यक्त किया। स्टंट निर्देशकों और कलाकारों के अनुसार, फिल्मों में कार स्टंट अन्य किसी भी एक्शन सीन की तुलना में अधिक खतरनाक और अप्रत्याशित होते हैं, भले ही सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हों। जाने-माने स्टंट निर्देशक श्याम कौशल के अनुसार, यह घटना बेहद दुखद है। कौशल ने 'डंकी', 'गदर 2', 'पोन्नियिन सेलवन', 'संजू', 'पद्मावत', 'बाजीराव मस्तानी' जैसी फिल्मों में काम किया है।

उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में पढ़ा और यह खबर बेहद दुखद है। मैंने उनके साथ काम नहीं किया है, लेकिन स्टंट समुदाय एक परिवार जैसा होता है। कार स्टंट में इंसान और मशीन दोनों की भूमिका होती है, और थोड़ी सी भी चूक भारी पड़ सकती है। स्टंट जोखिम भरे होते हैं। मूवी स्टंट आर्टिस्ट्स एसोसिएशन के महासचिव एजाज गुलाब ने भी इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। गुलाब के मुताबिक, कार और बाइक से जुड़े स्टंट हमेशा जोखिम भरे होते हैं। एक्शन निदेशक सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे स्टंट कोई अनुभवी कलाकार ही करें। एस एम राजू ऐसे स्टंट्स के लिए जाने जाते थे। यह घटना बेहद दुखद है। यह एसोसिएशन 1959 में गठित हुई थी और इसके करीब 600 सदस्य हैं। स्टंटमैन और अभिनेता सिल्वा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर राजू को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, हमारे बेहतरीन कार जंपिंग स्टंट कलाकारों में से एक एस एम राजू का निधन स्टंट करते समय हो गया। श्रद्धांजलि। हमारी यूनियन और फिल्म इंडस्ट्री उन्हें याद करेगी। स्टंटमैन शंकर ने कहा कि वह राजू की मौत से बेहद दुखी हैं। शंकर चेन्नई एक्सप्रेस में कार स्टंट करते समय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शंकर ने कहा कि वह 13 साल पहले जलने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे, फिर भी वह आज तक स्टंट करते रहे हैं। फिल्म जगत में 50 वर्षों से अधिक समय तक सक्रिय रहे पूर्व स्टंटमैन और निर्देशक राम शेट्टी ने भी शोक जताते हुए कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे हादसों में किसी की जान चली जाती है। मैंने उनके साथ काम नहीं किया है लेकिन उनका परिवार मेरी संवेदनाओं का पात्र है। आर्थिक मजबूरी के चलते लोग इस पेशे में आते हैं क्योंकि इसमें कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए। स्टंट कलाकार परवेज शेख ने कहा, राजू ने अपने करियर में कई बड़े स्टंट किए हैं। यह खबर दिल तोड़ने वाली है। जब वह कार स्टंट कर रहे थे तब यह हादसा हुआ। मैं उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। स्टंट करना जोखिम भरा होता है, और हर स्टंटमैन का परिवार जानता है कि उसे चोट लग सकती है। मालिक और आदिपुरुष जैसी फिल्मों में काम कर चुके स्टंट कलाकार अरविंद गुप्ता ने कहा, ह्यमैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता लेकिन यह काम हम पैसों के लिए करते हैं और यह जानलेवा भी हो सकता है।

वैश्विक मंच पर चमकती हिन्दी और क्षेत्रीय राजनीति की कुंठा

हिन्दी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की आत्मा, चेतना, अस्मिता और स्वाभिमान की प्रतीक है। यह भारतीय संस्कृति की वह अदृश्य डोर है, जो देश के कोने-कोने को जोड़ती है। दुर्भाग्यवश हिन्दी जब अपनी वैश्विक उड़ान भर रही है, उसी समय देश के भीतर कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक स्वार्थों के कारण हिन्दी का विरोध हो रहा है। खासकर महाराष्ट्र जैसे राज्य में, जहां मुंबई में हिन्दी फिल्मों का केंद्र है, वहां हिन्दी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी और हिन्दी बोलने वालों पर हमले की घटनाएं चिंताजनक हैं। यह विडंबना ही है कि एक ओर जहां दुनिया हिन्दी को सम्मान दे रही है, वहीं भारत में कुछ शक्तियां इसे राजनीतिक हथियार बना रही हैं।

यह सच है कि भारत में विविध भाषाओं और बोलियों का समृद्ध संसार है। संविधान 18वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता देता है। इनमें से हर भाषा का सम्मान और संरक्षण आवश्यक है लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली हिन्दी के खिलाफ वैमनस्य फैलाया जाए। हिन्दी को थोपे जाने की राजनीति और विरोध दोनों ही गलत हैं। भाषा का विकास संवाद और सहमति से होता है, न कि टकराव से। आज जब हिन्दी आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और साहित्यिक रूप से दुनिया में भारत की पहचान बन रही है, तब इसे विरोध का विषय बनाना केवल संकीर्ण राजनीति का परिचायक है। दुनियाभर में आज जब अपनी-अपनी भाषाओं को लेकर चिंता बढ़ रही है, ऐसे समय में हिन्दी न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छू रही है। एक ओर जहां सैंकड़ों भाषाएं लुप्त होने के कगार पर हैं, वहीं हिन्दी वैश्विक मंच पर तेजी से उभर रही है, जिसे लेकर हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए।

विश्व में लगभग 6900 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 35 से 40 प्रतिशत भाषाएं आज अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। इसके विपरीत हिन्दी अब दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। ह्यएथ्नोलॉगह्व की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, हिन्दी के 61.5 करोड़ मूल वक्ता हैं। यह आंकड़ा भाषा के प्रसार और इसकी प्रभावशीलता का प्रमाण है। मन्दारिन और अंग्रेजी के बाद हिन्दी की यह स्थिति केवल आंकड़ों की बात नहीं है बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति का वैश्विक स्वीकार भी है। वर्षों से हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र के मंच पर लाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। जून 2022 में जब संयुक्त राष्ट्र ने हिन्दी, उर्दू और बांग्ला में जानकारी उपलब्ध कराने की पहल की तो यह हिन्दी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। इससे स्पष्ट हुआ था कि वैश्विक संस्थाएं अब भारतीय भाषाओं की उपेक्षा नहीं कर सकती।

दुनिया के 50 से अधिक देशों में 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिन्दी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। अमेरिका, जर्मनी, रूस, फ्रांस, जापान, पोलैंड, नेपाल, फिजी, मॉरीशस जैसे देशों में हिन्दी के अध्ययन और शोध को लेकर विशेष रुचि देखी जा रही है। यूजीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में भारत में हिन्दी सीखने आने वाले विदेशी विद्यार्थियों की संख्या में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित फिजी में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। वहां फिजी हिन्दी महापरिषद जैसी संस्थाएं हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सक्रिय हैं। मॉरीशस में 2002 में स्थापित विश्व हिन्दी सचिवालय हिन्दी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार का सशक्त मंच बना हुआ है। यहां से विश्व हिन्दी पत्रिका और विश्व हिन्दी समाचार जैसे प्रकाशनों के जरिए हिन्दी की वैश्विक उपस्थिति मजबूत की जा रही है। रूस में भी हिन्दी साहित्य का प्रभाव गहराता जा रहा है। अनेक रूसी विद्वान तुलसीदास, प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा जैसे भारतीय लेखकों के साहित्य का रूसी में अनुवाद कर रहे हैं। रूस के कई विश्वविद्यालयों में हिन्दी भाषा और साहित्य का व्यापक अध्ययन होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि साहित्यिक दृष्टि से भी हिन्दी की जड़ें वैश्विक धरातल पर गहरी हो रही हैं।

हमें यह समझना होगा कि भारत के किसी भी राज्य में हिन्दी का विरोध करना भारत की एकता और संस्कृति पर हमला है। भाषा को विभाजन का नहीं, समावेशन और संवाद का साधन बनाना चाहिए। जब दुनिया हिन्दी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है तो हमें भी अपनी भाषायी चेतना को व्यापक बनाना होगा। हिन्दी किसी एक राज्य या क्षेत्र की नहीं, पूरे भारत की है। इसका विरोध उस भारतीयता का विरोध है, जो हिन्दी के जरिए दुनियाभर में फैल रही है। यह समय हिन्दी को राजनीति की भेंट चढ़ाने का नहीं, इसके वैश्विक उभार को समर्थन देने का है। इसलिए हमें हिन्दी को अपमानित नहीं बल्कि इसके इस उज्जवल भविष्य पर गर्व करना चाहिए।

हिन्दी को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी सम्मान दिया है। बच्चा, अच्छा, दादागिरी, पंडित, जुगाड़, गुलाब जामुन जैसे अनेक हिन्दी शब्द अब इस प्रतिष्ठित शब्दकोश का हिस्सा बन चुके हैं। यह उस सांस्कृतिक प्रभाव की मान्यता है, जो हिन्दी शब्दों के जरिए दुनिया में फैल रहा है। अमेरिका की ग्लोबल लैंग्वेज मॉनीटर संस्था हिन्दी की शब्दसंपदा को समृद्ध बता चुकी है। एक अनुमान के अनुसार हिन्दी में 1.25 लाख से अधिक शब्द हैं। वहीं, अमेरिका की 2023 की जनगणना रिपोर्ट बताती है कि वहां हिन्दी बोलने वालों की संख्या 10 लाख से अधिक हो चुकी है। 2011 की तुलना में यह वृद्धि अभूतपूर्व है। बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा ने भी हिन्दी के वैश्विक विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिन्दी फिल्मों की लोकप्रियता आज अमेरिका, इंग्लैंड, यूएई, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, तुर्की तक फैली है। कई देशों में हिन्दी फिल्मों के रेडियो चौनल, टीवी चैनल, फिल्म समारोह और लाइव शो आयोजित किए जाते हैं, जो हिन्दी को सांस्कृतिक राजदूत के रूप में प्रस्तुत करते हैं।

हिन्दी की लोकप्रियता को सोशल मीडिया ने भी एक नई ऊंचाई दी है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर हिन्दी सामग्री का विस्तार प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। 2024 की एक रिपोर्ट बताती है कि हिन्दी इंटरनेट उपयोगकताओं की संख्या 20 करोड़ पार कर चुकी है। गूगल के अनुसार, हिन्दी कंटेंट की वार्षिक वृद्धि दर 94 प्रतिशत है जबकि अंग्रेजी की घटती जा रही है। अब ई-कॉमर्स और तकनीक की दुनिया में भी हिन्दी एक मजबूत बाजार भाषा बन चुकी है। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियां भी अब हिन्दी में सेवाएं दे रही हैं। डेलॉइट की 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 65 प्रतिशत ऑनलाइन उपभोक्ता अब हिन्दी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी लेना पसंद करते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हिन्दी का आर्थिक मूल्य भी तेजी से बढ़ रहा है। गूगल ट्रांसलेट, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर, वॉयस असिस्टेंट्स, एआई चैटबॉट्स और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हिन्दी को प्रमुखता दी जा रही है। तकनीकी उपकरणों में हिन्दी इनपुट और आउटपुट की सुविधा अब आम बात हो चुकी है। भारत के डिजिटल इंडिया अभियान में भी हिन्दी की प्रमुख भूमिका है।

हिन्दी की वैश्विक प्रतिष्ठा को विश्व हिन्दी सम्मेलन जैसे आयोजन भी मजबूती दे रहे हैं। 1975 से अब तक यह सम्मेलन भारत, मॉरीशस, अमेरिका, यूके, त्रिनिदाद, फिजी जैसे देशों में आयोजित हो चुका है। इन आयोजनों में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इतिहास गवाह है कि महात्मा गांधी ने हिन्दी को राष्ट्र की आत्मा बताते हुए इसे राष्ट्रीय एकता का आधार कहा था। भारत सरकार द्वारा 1963 में स्थापित केन्द्रीय हिन्दी संस्थान अब हिन्दी में उच्च शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यह संस्थान प्रत्येक वर्ष ह्यहिन्दी सेवी सम्मानह्व प्रदान करता है, जो हिन्दी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिए जाते हैं।

बहरहाल, हमें यह समझना होगा कि भारत के किसी भी राज्य में हिन्दी का विरोध करना भारत की एकता और संस्कृति पर हमला है। भाषा को विभाजन का नहीं, समावेशन और संवाद का साधन बनाना चाहिए। जब दुनिया हिन्दी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है तो हमें भी अपनी भाषायी चेतना को व्यापक बनाना होगा। हिन्दी किसी एक राज्य या क्षेत्र की नहीं, पूरे भारत की है। इसका विरोध उस भारतीयता का विरोध है, जो हिन्दी के जरिए दुनियाभर में फैल रही है। यह समय हिन्दी को राजनीति की भेंट चढ़ाने का नहीं, इसके वैश्विक उभार को समर्थन देने का है। इसलिए हमें हिन्दी को अपमानित नहीं बल्कि इसके इस उज्जवल भविष्य पर गर्व करना चाहिए।

घूँघट की बगावत

20 जुलाई 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

ट्रंप प्रशासन द्वारा घोषित टैरिफ युद्ध : स्पष्टता का पूर्णतः अभाव

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के साथ ही दुनिया के लगभग समस्त देशों के साथ ट्रम्प प्रशासन द्वारा टैरिफ युद्ध की घोषणा कर दी गई है। अमेरिका में विभिन्न देशों से होने वाले आयात पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर एवं टैरिफ की दरों में बार बार परिवर्तन कर तथा इन टैरिफ की दरों को लागू करने की तिथि में परिवर्तन कर ट्रम्प प्रशासन टैरिफ युद्ध को किस दिशा में ले जाना चाह रहा है, इस सम्बंध में अब स्पष्टता का पूर्णतः अभाव दिखाई देने लगा है। अब तो विभिन्न देशों को ऐसा आभास होने लगा है कि अमेरिकी प्रशासन विभिन्न देशों पर टैरिफ की दरों के माध्यम से अपना दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है ताकि ये देश अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अमेरिकी शर्तों पर शीघ्रता के साथ सम्पन्न करें।

राष्ट्रपति ट्रम्प द्वारा कई बार यह घोषणा की गई है कि भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता शीघ्र ही सम्पन्न किया जा रहा है। अमेरिका एवं भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से भारतीय प्रतिनिधि मंडल अमेरिका में गया था तथा निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक वहां रहा एवं ऐसा कहा जा रहा है कि द्विपक्षीय समझौते के अंतिम रूप को अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है परंतु अभी तक अमेरिका द्वारा अमेरिका एवं भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की घोषणा नहीं की जा रही है। हालांकि, इस बीच अमेरिका द्वारा कई देशों के विरुद्ध टैरिफ की दरों को बढ़ा दिया गया है। विशेष रूप से जापान एवं दक्षिणी कोरिया से अमेरिका को आयात होने वाली वस्तुओं पर 1 अगस्त 2025 से 25 प्रतिशत की दर से टैरिफ लगाया जाएगा। इसी प्रकार, 12 अन्य देशों से अमेरिका में होने वाले आयात पर भी टैरिफ की बढ़ी हुई नई दरें लागू किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस सम्बंध में अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन 14 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को पत्र भी लिखा है। इस सूची में भारत का नाम शामिल नहीं है।

पूर्व में अमेरिका द्वारा चीन से आयात होने वाले उत्पादों पर भारी भरकम टैरिफ की घोषणा की गई थी। चीन ने भी अमेरिका से होने वाली आयातित वस्तुओं पर लगभग उसी दर पर टैरिफ लागू करने की घोषणा कर दी थी। साथ ही, चीन ने विभिन्न देशों को दुर्लभ खनिज पदार्थों (रेयर अर्थ मिनरल) के निर्यात पर रोक लगा दी थी। अमेरिका में चीन के इस निर्णय का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था जिसके दबाव में अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार समझौता करते हुए चीन से आयात होने वाली विभिन्न वस्तुओं पर टैरिफ की दरों को तुरंत कम कर दिया। अमेरिका द्वारा इसी प्रकार का एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता ब्रिटेन के साथ भी सम्पन्न किया जा चुका है। पूर्व में, ट्रम्प प्रशासन ने 90 दिवस की अवधि में 90 देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने की बात कही थी तथा 90 दिवस की समयावधि 9 जुलाई को समाप्त होने के पश्चात भी केवल दो देशों ब्रिटेन एवं चीन के साथ ही द्विपक्षीय व्यापार समझौता सम्पन्न हो सका है। भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा चुका है परंतु इसकी अभी तक घोषणा नहीं की गई है। द्विपक्षीय समझौते के लिए शेष देशों पर दबाव बनाने

की दृष्टि से ही इन देशों से अमेरिका को होने वाले आयात पर टैरिफ की दरों को एक बार पुनः बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है और इन बढ़ी हुई दरों को 1 अगस्त 2025 से लागू करने की योजना बनाई गई है।

वैश्विक स्तर पर अमेरिका द्वारा छेड़े गए इस टैरिफ युद्ध से निपटने के लिए भारत एक विशेष रणनीति के अंतर्गत कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत ने वैश्विक मंच पर न तो अमेरिका के टैरिफ की दरों में वृद्धि सम्बंधी निर्णयों की आलोचना की है और न ही भारत में अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। बल्कि, भारत ने तो अमेरिका से आयात होने वाली कुछ विशेष वस्तुओं पर टैरिफ को कम कर दिया है। दरअसल, भारत इस समय विकास के उस चक्र में पहुंच गया है जहां पर भारत को अपना पूरा ध्यान आर्थिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। भारत को यदि वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल करना है तो आगे आने वाले लगभग 20 वर्षों तक लगातार लगभग 8 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर को बनाए रखना अति आवश्यक है। इसलिए भारत एक विशेष रणनीति के अंतर्गत अपने आर्थिक विकास पर अपना ध्यान केंद्रित करता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के रूस के साथ भी अच्छे सम्बंध हैं तो अमेरिका से भी अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील है। भारत के इजराइल के साथ भी अच्छे सम्बंध हैं तो ईरान के साथ भी भारत के व्यापारिक सम्बंध हैं। रूस एवं यूक्रेन युद्ध के बीच भी भारत ने दोनों देशों के साथ अपना संतुलित व्यवहार बनाए रखा है। इसी कड़ी में, चीन के साथ भी आवश्यकता अनुसार बातचीत का दौर जारी रखा जा रहा है, बावजूद इसके कि कई बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चीन अप्रत्यक्ष रूप से भारत के विरुद्ध कार्य करता हुआ दिखाई देता है।

अभी हाल ही में चीन ने भारत को दुर्लभ खनिज पदार्थों (रेयर अर्थ मिनरल) की आपूर्ति पूर्णतः रोक दी है। साथ ही, मानसून का मौसम भारत में प्रारम्भ हो चुका है एवं भारत में कृषि क्षेत्र में गतिविधियां अपने चरम स्तर पर पहुंच गई हैं, ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण समय पर चीन द्वारा भारत को उर्वरकों की आपूर्ति पर परेशानियां खड़ी की जा रही हैं। चीन द्वारा समय समय पर भारत के लिए खड़ी की जा रही विभिन्न समस्याओं के हल हेतु भारत ने विश्व के पूर्वी देशों एवं विश्व के दक्षिणी भाग में स्थित देशों की ओर रूख किया है। अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घाना, नामीबिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, त्रिनिदाद एवं टोबैगो जैसे देशों की यात्रा इस उद्देश्य से सम्पन्न की है ताकि दुर्लभ खनिज पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इन देशों में दुर्लभ खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

भारत में 140 करोड़ नागरिकों का विशाल बाजार उपलब्ध है, जिसे अमेरिका एवं चीन सहित विश्व का कोई भी देश नजर अन्दाज नहीं कर सकता है। यदि अमेरिका एवं चीन भारत के साथ अपने सम्बन्धों को किसी भी कारण से बिगाड़ने का प्रयास करते हैं तो लम्बी अवधि में इसका नुक्सान इन्हीं देशों को अधिक होने जा रहा है है क्योंकि ऐसी स्थिति में वे भारत के विशाल बाजार से वंचित हो जाने वाले हैं। भारत तो वैसे भी पिछले लम्बे समय से आत्मनिर्भर होने का लगातार प्रयास कर रहा है एवं कई क्षेत्रों में भारत आज आत्मनिर्भर बन भी गया है। अतः भारत की निर्भरता अन्य देशों पर अब कम ही होती जा रही है। भारत आज फार्मा, ऑटो, कृषि, इंजीनीयरिंग, टेक्नॉलोजी, स्पेस तकनीकी, सूचना प्रौद्योगिकी, आदि क्षेत्रों में बहुत आगे निकल चुका है। आज भारत विकास के उस पड़ाव पर पहुंच चुका है, जिसकी अनदेखी विश्व का कोई भी देश नहीं कर सकता है। भारत को हाल ही में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में कच्चे तेल के अपार भंडार होने का भी पता लगा है। एक अनुमान के अनुसार, यह भंडार इतने विशाल हैं कि आगामी 70 वर्षों तक भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति होती रहेगी। इसी प्रकार, भारत में कर्नाटक स्थित कोलार स्वर्ण खदानों में भी एक बार पुनः खुदाई का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। आरम्भिक अनुमान के अनुसार, प्रतिवर्ष लगभग 750 किलोग्राम स्वर्ण की आपूर्ति भारत को इन खदानों से हो सकती है।

पूरे विश्व में आज केवल भारत ही युवा देश की श्रेणी में गिना जा रहा है क्योंकि भारत की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम आयुवर्ग में हैं तथा लगभग 40 प्रतिशत आबादी 15 से 35 वर्ष के आयुवर्ग में शामिल हैं। अतः एक तरह से भारत आज विश्व के लिए श्रम का आपूर्ति केंद्र बन गया है। लम्बे समय से रूस एवं यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बाद जब इन देशों में आधारभूत सुविधाओं को पुनर्विकसित करने का कार्य प्रारम्भ होगा तो इन्हें भारतीय श्रमिकों एवं इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ने जा रही है, एक अनुमान के अनुसार अकेले रूस द्वारा में लगभग 10 लाख भारतीयों की मांग की जा सकती है। इसी प्रकार, इजराइल एवं हम्मास तथा ईरान के बीच युद्ध की समाप्ति के पश्चात इन देशों में भी बुनियादी ढांचे को पुनः मजबूत करने का कार्य जब प्रारम्भ होगा तो इन देशों को भी भारतीय नागरिकों की आवश्यकता पड़ेगी। इजराइल, जापान सिंगापुर एवं ताइवान आदि देशों द्वारा तो पूर्व में भी भारतीय इंजीनियरों की मांग की जाती रही है। अमेरिका, ब्रिटेन एवं अन्य यूरोपीय देशों में तो डॉक्टर एवं इंजीनियरों की भारी मांग पूर्व से ही बनी हुई है। अतः आज भारत पूरे विश्व में डॉक्टर, इंजीनियर तथा श्रमिक उपलब्ध कराने के मामले बहुत आगे है। अतः भारत की इस ताकत की अनदेखी आज कोई भी देश नहीं कर सकता है।

'नाथपंथ और योग' पुस्तक के मुख्य आवरण का कुलपति ने किया विमोचन

गोरखपुर (जीकेबी)। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के महायोगी गुरु श्रीगोरक्षनाथ शोधपीठ द्वारा संपादन शोधपीठ के उपनिदेशक डॉ. कुशल नाथ मिश्रा एवं सहायक निदेशक डॉ. सोनल सिंह प्रकाशित पुस्तक 'नाथपंथ और योग' के मुख्य आवरण का विमोचन विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन द्वारा किया गया। इस पुस्तक में भारत के विभिन्न विद्वानों के योग व नाथपंथ पर आधारित शोध लेखों को संकलित किया गया है। विमोचन के अवसर पर कुलपति प्रो. टंडन ने कहा कि यह पुस्तक योग एवं नाथ परंपरा से जुड़े शोधार्थियों व अध्येताओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने इस कार्य के लिए संपादकों की सराहना की।

अवैध घुसपैठियों के खिलाफ भी हो कड़ी कार्रवाई

बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान- एसआई आर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लंबी सुनवाई करने और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए जरूरी मान्य दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को भी शामिल करने पर विचार करे। देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग से कई अहम मुद्दों पर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक नहीं लगाई है। यानी चुनाव आयोग द्वारा चलाया गया यह विशेष अभियान चलता रहेगा। लेकिन अदालत ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को भी मान्यता देने का सुझाव देकर बिहार के आम मतदाताओं की मुश्किलों को भी आसान करने का प्रयास किया है। इससे पूरी प्रक्रिया आसान होगी और वोटर लिस्ट को लेकर जिस तरह की आशंकाएं पैदा हो रही है, उसे भी कम करने में मदद मिलेगी।

दरअसल, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग का काम ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल कर, उन्हें वोट देने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना है। चुनाव आयोग का काम वोटर लिस्ट से जीवित मतदाताओं का नाम हटाना नहीं है। चुनाव आयोग किसी भी मतदाता से उसका मताधिकार कतई नहीं छीन सकता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान, बिहार सहित पूरे देश में आधार कार्ड को जिस तरह से बाकी सभी कार्डों, बैंक खातों और सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है, उसके बाद आधार कार्ड को पूरी तरह से खारिज करने से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। बिहार में कई जिलों में इस अभियान के तहत

आधार कार्ड को स्वीकार किया जा रहा था और कई जिलों में नहीं किया जा रहा था, जिससे कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में यह बहुत जरूरी माना जा रहा था कि चुनाव आयोग कोई बीच का रास्ता निकाले।

सुप्रीम कोर्ट ने भले ही रक्फ़पर रोक नहीं लगाई हो लेकिन टाइमिंग को लेकर जो सवाल पूछे हैं, उससे चुनाव आयोग की इस पूरी कवायद पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और चुनाव आयोग के इस अभियान को लेकर सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे। हालांकि जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाला बागची की पीठ ने साफ-साफ कहा कि वे संवैधानिक संस्था को वह करने से नहीं रोक सकते जो उसे करना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपना जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है। वहीं याचिकाकाताओं को उसके एक सप्ताह बाद जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

यह मामला केवल बिहार तक ही सीमित रहने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में दूसरे राज्यों में मतदाता सूची की समीक्षा कैसे होगी, यह बिहार के मॉडल पर निर्भर करेगा इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर सबकी नजरें बनी रहेंगी।

हालांकि यह भी एक कड़वा सच है कि बिहार सहित देश के कई राज्यों में अवैध घुसपैठियों की भरमार हो गई है। भारत 70 के दशक से ही बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों से त्रस्त रहा है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान म्यामांर से भी रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ देश में बढ़ती जा रही है। देश के कई जिलों में इन अवैध घुसपैठियों की वजह से हालात काफी भयावह हो गए हैं,इसे नकारा नहीं जा सकता है। बिहार के भी कई जिले, अवैध घुसपैठियों से भरे पड़े हैं, इस सच्चाई को भी खारिज नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि बिहार के सीमांचल इलाकों में अवैध घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ी है लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार का हर जिला बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों से पीड़ित है। बिहार के मिथिलांचल इलाके में भी अवैध घुसपैठियों की संख्या खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन इस समस्या का समाधान कर पाना चुनाव आयोग के वश में नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाना होगा। एक तरफ सीमा से होने वाली घुसपैठ को हर हाल में रोकना होगा, दूसरी तरफ सीमावर्ती जिलों के प्रशासनिक ढांचे को भ्रष्टाचार मुक्त और चुस्त-दुरुस्त बनाना होगा। इसके साथ ही देश में घुस चुके घुसपैठियों को देश से हर कीमत पर बाहर भगाने के लिए भी एक व्यापक अभियान चलाना होगा। यह समय की मांग है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर भगाने के लिए जल्द से जल्द इस तरह का अभियान बड़े पैमाने पर शुरू किया जाए।

फिल्म समीक्षा

मालिक एक कमजोर कहानी ...राजकुमार राव की जबरदस्त परफार्मेंस ने लोगों को बांधे रखा

पुलकित द्वारा निर्देशित और राजकुमार राव की गैंगस्टर ड्रामा'मालिक' 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसमें राजकुमार राव, प्रोसेनजीत, मानुषी छिल्लर, सौरभ शुक्ला और स्वानंद किरकिरे मुख्य भूमिकाओं में हैं। राजकुमार एक गैंगस्टर की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं, और कहना होगा कि वह फिल्म में बेहद खतरनाक लग रहे हैं। 'बोसः डेड/अलाइव' के बाद, 'मालिक' राजकुमार और पुलकित की दूसरी जोड़ी है। फिल्म में प्रोसेनजीत चटर्जी, अंशुमान पुष्कर, स्वानंद किरकिरे और सौरभ शुक्ला भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। आइए देखते हैं कि क्या 'मालिक' दर्शकों को प्रभावित कर पाती है या नहीं।

कहानी

यह कहानी महत्वाकांक्षा और विश्वासघात से प्रेरित एक साधारण व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों की दलदली गहराइयों में यात्रा को दर्शाती है। कहानी इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे राजनीति, भ्रष्टाचार और वफादारी आपराधिक दुनिया में एक साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे-जैसे मालिक शोहरत की बुलंदियों को छूता है और अपने फैसलों के प्रभावों की पड़ताल करता है। 1980 के दशक के प्रयागराज में स्थापित, यह फिल्म राव के कंधों पर तब तक रेंगती है जब तक कि सहायक कलाकार धीरे-धीरे और लगातार प्रभाव नहीं डालते। जहाँ पहला भाग उन संघर्षों और द्वंद्वों को दर्शाता है जिनसे मालिक सत्ता और कब्जे की सीढ़ियाँ चढ़ता है, वहीं दूसरा भाग उसके परिणामों को उजागर करता है क्योंकि उसका रास्ता और भी खतरनाक होता जाता है। राजनीति, भ्रष्टाचार और सत्ता के खेल में उसकी दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। फिल्म दिखाती है कि कैसे एक इंसान की इच्छाएँ उसे धीरे-धीरे एक अंधे रास्ते पर ले जाती हैं, जहाँ उसे हर कदम पर त्याग करना पड़ता है। यह फिल्म न केवल अपराध की कहानी कहती है, बल्कि एक भावनात्मक सफर भी है, जिसमें कई मोड़ और उतार-चढ़ाव हैं।

लेखन और निर्देशन

मालिक की कहानी ज्योत्सना नाथ और पुलकित ने लिखी है। दोनों ने एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश की है जो बेरहम एक्शन, रोमांस, दोस्ती और विश्वासघात से भरपूर हो। आदमी के जुनून और सत्ता की भूख में झूठों को जोड़ना एक अच्छा कदम था, लेकिन लेखकों ने दूसरे भाग को संक्षिप्त रखने में चूक की। ढाई घंटे लंबी फिल्म दूसरे भाग में दर्शकों को बोर कर सकती है। इसके अलावा, प्रोसेनजीत चटर्जी का किरदार भी कमजोर लिखा गया है। किरदार न तो मजबूत था और न ही उसमें गहराई। बंगाली एनकाउंटर पुलिस अधिकारी दास, मालिक से बस एक हफ़्ते छोटे थे। दूसरी ओर, हुमा कुरैशी का किरदार जरूरी नहीं था।

अभिनय

मालिक पूरी तरह से राजकुमार राव पर फि ल्माया गया है। वह किरदार में पूरी तरह से रम गए हैं। वह फिल्म की जान हैं और इसके लिए उन्हें 100 अंक मिलते हैं। एक्शन दृश्यों में उनकी आवाज और बॉडी लैंग्वेज पर पकड़ प्रभावशाली है। दूसरी ओर, मानुषी छिल्लर कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहीं। एक अभिनेत्री के रूप में उन्होंने खुद को बेहतर बनाया है। प्रोसेनजीत चटर्जी अपने दमदार अभिनय से फिल्म में जान डाल देते हैं। सौरभ शुक्ला, स्वानंद किरकिरे और सौरभ सचदेवा ने सहायक भूमिकाओं में अच्छा काम किया है। अंशुमान पुष्कर, मालिक का एक सरप्राइज पैकेज हैं। राजकुमार राव के साथ उनके कुछ अहम सीन आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते।

फैसला

मालिक का दमदार मुख्य अभिनय, यथार्थवादी कहानी और जबरदस्त दुनिया-निर्माण इसे अलग बनाती हैं, हालाँकि यह गैंगस्टर शैली की कोई क्रांतिकारी फिल्म नहीं है। गंभीर आपराधिक ड्रामा के प्रशंसक इस बेहतरीन और भावनात्मक रूप से प्रभावशाली फिल्म को देखने लायक पाएंगे। एक मजबूत गैंगस्टर कहानी, जो दमदार अभिनय से प्रेरित है, आपको कमियों को नजरअंदाज करने पर मजबूर कर देगी। राजकुमार राव और पुलकित की मालिक 5 में से 3 स्टार की हकदार है।

7 जनवरी 1938 को सरोजा का जन्म बेंगलुरु में हुआ था। वो कन्नड़ सिनेमा का सबसे बड़ा नाम थीं। उन्हें कन्नड़ सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार का दर्जा भी दिया गया था। कन्नड़ फिल्मों के अलावा उन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्में भी की थीं। एक्ट्रेस ने अपने लंबे और सफल करियर में 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। इनमें से 160 से ज्यादा फिल्मों में वो बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई थीं। शानदार अभिनय के लिए उन्हें 1969 में पद्म श्री और 1992 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

जाते-जाते नेत्रदान जैसा पुण्य कार्य कर गईं बी.सरोजा देवी

मुंबई। सोमवार, 14 जुलाई को सिने जगत से दुखद खबर सामने आई थी। दक्षिण भारतीय सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस बी सरोजा देवी का सोमवार को निधन हो गया था। वेटरन एक्ट्रेस ने 87 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। अब एक्ट्रेस की आंखें उनकी इच्छा के अनुसार दान की गईं हैं। मृत्यु के बावजूद एक्ट्रेस की आंखें दुनिया देख पाएगी। बी सरोजा देवी की इच्छा थी कि उनके निधन के बाद उनकी आंखों को दान कर दिया जाए, जिससे कि किसी नेत्रहीन को नई रोशनी मिल सके। एक्ट्रेस के परिवार ने ये नेक कार्य एक्ट्रेस के निधन के ठीक बाद कर दिया। उनकी आंखों को नारायण नेत्रालय को दान किया गया है। बी सरोजा देवी के नेत्रदान को लेकर नारायण नेत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, बी सरोजा देवी ने पांच साल पहले नेत्रदान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। वो जब जांच के लिए आई थीं तब हमारे चेयरमैन से अपनी आंखें दान करने की बात कही थी। उन्होंने इसके लिए एक कार्ड बनवाया था और पंजीयन भी करवाया था।

वहीं दिग्गज एक्ट्रेस के बेटे गौतम ने भी मीडिया से बात करते हुए अहम जानकारी शेयर की है उन्होंने बताया, मां की आंखें दान कर दी गई हैं और जल्द ही उनका प्रत्यारोपण कर दिया जाएगा। फिलहाल डॉक्टर्स ने कॉर्निया लिया है और दोनों कॉर्निया अच्छी स्थिति में हैं।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादकः पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com